1

सामान्य–पुनरीक्षा

घटनाओं की पुनरीक्षा

(क) वृहद् आर्थिक सिंहावलोकन

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा 31 जनवरी, 2003 को निर्गत वर्ष 2001–02 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001–02 में 1993–94 के स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत की दृष्टि से सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) 5.6 प्रतिशत बढ़ा जो फरवरी 2002 में अनुमानित 5.4 प्रतिशत की तुलना में है। वर्ष 2001–02 के उच्चतर वृद्धि अनुमान विशेषरूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह प्रारंभिक आशंकाओं की तुलना में वर्ष 2000–01 के लिए अधिक सामान्य वृद्धि अवमंदन के संशोधित अनुमान की पृष्ठभूमि में प्राप्त हुए है। वर्ष 2000–01 में 1993–94 के स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत की दृष्टि से स.घ.उ. की वृद्धि 4.4 प्रतिशत है जो पिछले 4.0 प्रतिशत के अनुमान की तुलना में है। मुख्य वृहद आर्थिक पैरामीटरों की प्रवृत्तियां सारणी 1.1 तथा चित्र 1.1 में दी गई हैं।

1.2 वर्ष 2001–02 में देखी गई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी प्रारंभ में अनुमानित तेजी से अधिक सुदृढ़ थी। 1993–94 के स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर त्रैमासिक स.घ.उ. के आंकड़े, जो केवल वर्ष 2002–03 के पूर्वार्ध के लिए उपलब्ध हैं, यह संकेत देते हैं कि चालू वर्ष की पहली और दूसरी तिमाहियों में वर्षानुवर्ष स.घ.उ. 6 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत दरों पर बढ़ा है जो पिछले वर्ष की इन्हीं अवधियों में दर्ज क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से अधिक हैं। परन्तु मानसून की असफलता ने कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे दिनांक 7 फरवरी, 2003 को सी.एस.ओ. द्वारा निर्गत अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सहयोगी स.घ.उ. में 3.1 प्रतिशत की गिरावट हुई। चालू वर्ष में स.उ.घ. की समग्र वृद्धि केवल 4.4 प्रतिशत होने की संभावना है। कृषि के कारण वर्ष 2002–03 में इस मंदी ने वर्ष 2001–02 और 2002–03 के बीच उद्योग एवं सेवाओं में क्रमशः 3.3 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत से 7.1 प्रतिशत के वृद्धि निष्पादन के समस्त सुधारों को प्रभावित किया है।

1.3 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू अर्थव्यवस्था में विद्यमान अनेक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के पूर्वार्ध में निरन्तर वृद्धि सुधार महत्वपूर्ण है। वैश्विक आर्थिक क्रियाकलापों एवं विश्व व्यापार में सुधार का दृष्टिकोण असंतोषजनक रहा है। लैटिन अमरीका और टर्की में डावांडोल परिस्थितियों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह प्रभावित हुए हैं। ईराक अलगाव के साथ भू–राजनैतिक दशाएं काफी अस्थिर रही हैं। इसके अलावा दो दशकों में मानसून की अत्यधिक कमी से देश प्रभावित रहा है।

1.4 वृद्धि में सुधार के साथ निम्न मुद्रास्फीति, व्यवस्थित मुद्रा बाजार दशाओं एवं संतोषजनक आरक्षित निधियों के संदर्भ में निरंतर वृहद आर्थिक स्थायित्व बना रहा। गत समय में, खाद्यान्नों की कीमतों एवं उपलब्धता पर सूखे के प्रभाव के कारण गरीबों पर इसका विशेषरूप से बुरा असर पड़ा था। चालू वर्ष में, अल्प मानसून के बावजूद अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता में कमी नहीं थी अथवा कीमतों में भी अधिक उछाल नहीं आया। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) पर आधारित 52 सप्ताह की औसत मुद्रास्फीति दर जनवरी, 2003 के मध्य में केवल 2.6 प्रतिशत थी। वर्ष के अधिकांश हिस्से में प्राथमिक उत्पादों के मूल्य 4 प्रतिशत से नीचे रहे जबकि विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति लगभग 3 प्रतिशत थी। पैट्रोलियम उत्पादों के लिये बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली अपनाना भी विघटन रहित था क्योंकि ईंधन समूह से संबंधित मुद्रास्फीति अधिकांश वर्ष में मुश्किल से 5 प्रतिशत के आसपास थी। परन्तु, खाड़ी संबंधी पिछली अनिश्चितता ने जनवरी, 2003 के मध्य में ईंधन की कीमत में मुद्रास्फीति

सारणी 1.1 : मुख्य संकेतक

मद	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
	संपूर्ण मूल्य				पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन			
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (उपादान लागत पर) (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	1746.5	1900.3 अ	2081.4क्यू.	2217.8अअ	10.3	8.8 अ	9.5 Q	6.6अअ
1993-94 की कीमतों पर	1136.8	1186.3 अ	1257.0क्यू.	1309.9अअ	6.2	4.3 अ	6.0 Q	4.2अअ
सकल घरेलू उत्पाद (उपादान लागत पर) (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	1761.9	1917.7 अ	2094.0क्यू.	2236.1अअ	10.2	8.8 अ	9.2 Q	6.8अअ
1993-94 की कीमतों पर	1148.4	1198.7 अ	1265.4क्यू.	1320.7अअ	6.1	4.4 अ	5.6 Q	4.4अअ
कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रक (हजार करोड़ रुपए) (1993-94 की कीमतों पर)	286.98	285.88	302.05क्यू.	292.63अअ	0.3	-0.4	5.7 Q	-3.1अअ
कृषि उत्पादन का सूचकांक (1)	176.8	167.3 अ	177.1 अ	156.0 अ	-0.6	-5.4 अ	5.9 अ	-11.9 अ
खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	209.8	199.5	212.0 अ	183.2 अ	3.0	-4.9	6.3 अ	-13.6 अ
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक(2)	154.9	162.6	167.0	170.5 **	6.7	5.0	2.7	5.3 #
उत्पन्न बिजली (बिलियन के.डब्ल्यू.एच.)	480.7	499.5	515.2	397.6 **	7.2	3.9	3.1	3.7 **
थोक मूल्य सूचकांक (3)	150.9	159.2	161.8	167.9 *	6.5	4.9	1.6	4.4 *
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (4)	434.0	445.0	468.0	484@	4.8	2.5	5.2	3.2@
मुद्रा आपूर्ति (एम 3)(5) (हजार करोड़ रुपए)	1,124.2	1,313.2	1,500.0	1689.1(6)	14.6	16.8	14.2	15.7(6)
वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रुपए)	2,15,236	2,30,873	2,45,200	2,13,225 **	20.7	7.3	6.2	17.5 **
(मिलियन अमरीकी डालर)	49,671	50,536	51,413	43,882 **	17.2	1.7	1.7	14.5 **
वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रुपए)	1,59,561	2,03,571	2,09,018	1,85,211 **	14.2	27.6	2.7	23.4 **
(मिलियन अमरीकी डालर)	36,822	44,560	43,827	38,115 **	10.8	21.0	-1.6	20.4 **
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (7) (करोड़ रुपए)	1,52,924	1,84,482	2,49,118	3,34,065(8)	21.9	20.6	35.0	47.7(8)
(मिलियन अमरीकी डालर)	35,058	39,554	510,49	69,888(8)	18.8	12.8	29.1	50.1(8)
विनिमय दर (रुपए/अमरीकी डालर) (9)	43.33	45.68	47.69	48.54(10)	-2.9	-5.1	-4.2	-2.16(10)

टिप्पणी : सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े उपादान लागत के अनुसार हैं (नई शृंखला आधार वर्ष = 1993-94)

क्यू-त्वरित अनुमान अ.अ.-अग्रिम अनुमान अ-अनन्तिम

*18.1.2003 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)। @ दिसंबर 2002 ** अप्रैल-दिसम्बर 2002 # अप्रैल-नवम्बर 2002

1. कृषि उत्पादन का सूचकांक (46 फसलों का, रोपण फसलों सहित) आधार 1981-82 को समाप्त त्रय वर्ष = 100 (संशोधित)
2. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, (आधार 1993-94 = 100)
3. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1993-94 = 100)
4. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार 1982 = 100)
5. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।
6. 10 जनवरी 2003 की स्थिति के अनुसार वर्षानुवर्ष वृद्धि।
7. राजकोषीय वर्ष के अंत में बकाया।
8. जनवरी 2003 के अंत में।
9. प्रतिशत परिवर्तन अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की वृद्धि(+)/ह्रास (-) दर को दर्शाता है।
10. अप्रैल-जनवरी, 2002-2003 का औसत।

बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत पर ला दी। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.) द्वारा यथामापित मुद्रास्फीति वर्ष 2002–03 के प्रारंभ मे 4.7 प्रतिशत से कम होकर दिसम्बर, 2002 में 3.2 प्रतिशत हो गई। भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के पास गेहूं (1 जनवरी, 2003 को 28.8 मिलि. टन) और चावल (1 जनवरी, 2003 को 19.4 मिलि. टन) के पर्याप्त भण्डार ने यद्यपि कृषि विविधीकरण एवं राजकोषीय सुदृढ़ता के कार्य को जटिल बना दिया, फिर भी इसने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने मे मदद की।

1.5 11 सितम्बर, 2001 की घटनाओं के बाद विश्व मुद्रा बाजारों की अस्थिरता के बावजूद समुचित एवं उचित समय पर किये गये नीति उपायों ने रुपये की विनिमय दर की अस्थिरता को सामान्य रखा जो वर्ष 2001–02 के दौरान प्रति अमरीकी डालर 46.56–48.85 रु. के बीच रही, अमरीकी डालर के संदर्भ में रुपये का औसत अवमूल्यन 4.0 प्रतिशत था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, मई, 2002 में प्रति अमरीकी डालर 49.06 रुपये के सर्वाधिक उच्च स्तर पर जाने के बाद, रुपया डालर के संदर्भ में सुदृढ़ हो गया और दिसम्बर 2002 के अंत में यह प्रति डालर 47.80 रुपये की विनिमय दर पर था जो मार्च, 2002 के अंत के स्तर की तुलना में 2.1 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि प्रदर्शित करता है। परंतु अप्रैल 2002 से जनवरी 2003 की अवधि के दौरान पौण्ड स्टर्लिंग, यूरो और येन के संदर्भ में रुपए का क्रमश: 8.9 प्रतिशत 14.9 प्रतिशत, और 7.4 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ जो इन मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के आंशिक रूप से कमजोर पड़ने की स्थिति का संकेत है।

1.6 मार्च, 2002 के अंत में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 51. 05 बिलियन अमरीकी डालर थीं जो मार्च, 2001 के अंत में 39.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 11.5 बिलियन अमरीकी डालर अधिक हैं। इस वृद्धि में से एक बड़ा हिस्सा (9.10 बिलियन अमरीकी डालर) वर्ष 2001–02 के उत्तरार्ध के दौरान प्राप्त किया गया। आरक्षित निधि वृद्धि में चालू वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में तेजी आई जब विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि जनवरी, 2003 के अंत में सर्वाधिक बढ़कर 73.58 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर आ गई जो मार्च, 2002 के अंत के स्तर की तुलना में 19.47 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया हाल का एक अध्ययन प्रदर्शित करता है कि चालू राजकोषीय वर्ष में नवम्बर, 2002 के अंत तक आरक्षित निधि वृद्धि के प्रमुख स्रोत चालू–खाते में अधिशेष, गैर–ऋण उत्पादक पूंजी प्रवाह और मूल्य अनुलाभ हैं। विदेश और भारत के बीच 3–4 प्रतिशत के ब्याज दर अंतरों के बावजूद ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि ऋण पूंजी के जरिये अंतरपणन अधिक था। इस प्रकार कम से कम नवम्बर 2002 तक, अंतरपणन ने संभवत: आरक्षित निधि के संचयन में प्रमुख भूमिका अदा नहीं की है। ऐसा अनुमान है कि लगभग दो तिहाई आरक्षित निधि वृद्धि गैर–ऋण पूंजी प्रवाहों के कारण थी। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि से विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों में आगे और छूट देने तथा अधिक पूंजी–खाता–परिवर्तनीयता की दिशा में क्रमिक रूप से बढ़ने में भी सहायता मिली है।

1.7 आरक्षित निधियों मे तीव्र वृद्धि आंशिक रूप से सुदृढ़ चालू खाते के परिणामस्वरूप थी। तेईस वर्षों के बाद भारत के वर्तमान भुगतान संतुलन खाते ने वर्ष 2001–02 में स.घ.उ. के 0.3 प्रतिशत के समतुल्य अधिशेष दर्ज किया। निर्यातों में वृद्धि न होने और गिरते हुए आयातों ने वर्ष 2001–02 में व्यापार घाटे को 0.5 प्रतिशतांक नीचे ला दिया। चालू खाते में अधिशेष मुख्यत: स.घ.उ. के 2.9 प्रतिशत के बराबर, 14.05 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर उत्प्लावक निवल अदृश्य अंतर्प्रवाहों के कारण हुआ है, जो पिछले दशक मे सर्वाधिक थे। मुख्यत: धनराशियों के भारी अंतर्प्रवाह के कारण चालू वर्ष में भी अदृश्य राशियां अच्छे परिणाम दिखा रही हैं। निर्यातों में तेजी से वृद्धि के साथ यह दूसरे अनुक्रमिक वर्ष में चालू खाते में अधिशेष होने की संभावना को पर्याप्त बढ़ा रहा है। डी जी सी आई एवं एस आंकड़ों के अनुसार डालर के संदर्भ में निर्यात इस समय (अप्रैल–दिसम्बर, 2002) 20.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। डालर के संदर्भ में वर्षानुवर्ष निर्यात दिसम्बर, 2002 में 34.3 प्रतिशत बढ़े। वैश्विक आर्थिक सुधार की धीमी गति और डालर के मुकाबले रुपये में मामूली मूल्यवृद्धि के बावजूद निर्यातों में तेजी आई है और इसने घरेलू औद्योगिक वृद्धि में योगदान किया है।

1.8 जहां व्यापारिक माल निर्यात वर्ष 2002–03 में संतोषजनक रूप से बढ़े हैं वहां सेवा निर्यात भी सफलता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा हैं जैसाकि वर्ष 2001–02 में 14 बिलियन अमरीकी डालर के निवल अदृश्य अंतर्प्रवाहों में प्रदर्शित होता है। विश्व वाणिज्यिक सेवा व्यापार में भारत का हिस्सा विश्व व्यापारिक माल व्यापार में भारत के हिस्से से

अधिक है। जहां साफ्टवेयर निर्यात सर्वविदित सफलता की कहानी हैं वहां भारत वित्तीय लेखाकरण, कॉल-सेंटर, बीमा दावों के प्रक्रियान्वयन और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जैसी सेवाओं में अनेक कार्यों के लिए अब एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। इन क्षेत्रों में वृद्धि के लिए पर्याप्त संभावना प्रतीत होती है।

1.9 भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एन.एफ.ए.) के आरक्षित निधि के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरने के साथ भुगतान संतुलन के सुदृढ़ीकरण का मौद्रिक क्षेत्रक में प्रभाव पड़ा है। आरक्षित निधि में निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का हिस्सा जो मार्चांत, 1991 की स्थिति के अनुसार 9.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 के अंत तक 78.1 प्रतिशत पर पहुंच गया था, 24 जनवरी, 2003 को 100.7 प्रतिशत हो गया जो ''करेंसी बोर्ड'' की स्थिति के समीप है। इसी तरह मुद्रा-एन.एफ.ए. अनुपात मार्चांत 1991 की स्थिति के अनुसार 14.4 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़कर 31 मार्च 2002 को 105.2 प्रतिशत और 24 जनवरी, 2003 को और बढ़कर 127.7 प्रतिशत पर पहुंच गया। नकदी निधि प्रबंधन के लिये विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में पर्याप्त वृद्धि को आर.बी.आई. के निवल घरेलू ऋण में गिरावट ने अंशत: प्रतिसंतुलित कर दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का क्रेडिट ऋणात्मक रहा और 24 जनवरी, 2003 तक आरक्षित मुद्रा 2.9 प्रतिशत बढ़ी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4.7 प्रतिशत की तुलना में है।

1.10 बहुविध मुद्रा अर्थात् आरक्षित मुद्रा के प्रति स्थूल मुद्रा ($एम_3$) का अनुपात जो पिछले वर्ष 4.3 से बढ़कर 4.4 हो गया था, 10 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार और आगे बढ़कर 4.8 हो गया। चालू वित्तीय वर्ष में 10 जनवरी, 2003 तक स्थूल मुद्रा में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (आई. सी.आई.सी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के आमेलन बाद निवल) जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 11.2 प्रतिशत की तुलना में है। 10 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार $एम_3$ की वर्षानुवर्ष वृद्धि पिछले वर्ष 14.5 प्रतिशत की तुलना में 12.8 प्रतिशत थी (आमेलन के बाद निवल)।

1.11 मुद्रा आपूर्ति की धीमी वृद्धि के बावजूद चालू वर्ष सुलभ नकदी की दशाओं वाला वर्ष रहा है। सरकारी प्रतिभूतियों की आय सहित ब्याज दरों में गिरावट और गैर खाद्य ऋण में वृद्धि के संकेत हैं। 10 जनवरी, 2003 तक गैर-खाद्य ऋण (आमेलन के बाद निवल) 11.4 प्रतिशत बढ़ गये जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.1 प्रतिशत की तुलना में हैं। औद्योगिक क्रियाकलाप में सुधार से गैर-खाद्य ऋण लेने में और वृद्धि हो सकती है। चालू वित्तीय वर्ष में खाद्य ऋणों में 7.1 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 33.0 प्रतिशत की वृद्धि थी, इसके मुख्य कारण चालू वर्ष में सूखा, तथा खाद्यान्नों का अधिक उठान था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्रक अग्रिम मार्च, 2002 के अंत में निवल बैंक ऋण के 43.1 प्रतिशत थे। निजी बैंकों के मामले में तदनुरूपी प्रतिशत 40.9 था जो 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। फिर भी कृषि क्षेत्रक के लिए निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रक उप-लक्ष्यों में कमी आई। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्वीकृतियों एवं संवितरणों में गिरावट का रूख देखा गया जिसके मुख्य कारण वित्तीय सहायता वाले परियोजना प्रस्तावों की संख्या में कमी होना, आई.डी.बी. आई. और आई.एफ.सी.आई. की कमजोर वित्तीय स्थिति और विश्वव्यापी बैंकिंग का प्रसार हैं।

1.12 अपेक्षतया निम्नतर मुद्रास्फीति के कारण वर्ष के दौरान ब्याज दरें कम बनी रहीं। आर.बी.आई. ने अक्तूबर, 2002 में बैंक दर 25 आधार बिन्दु कम करके 6.25 प्रतिशत कर दी। अपने वर्तमान स्तर के अनुसार बैंक दर 1973 से आज तक सबसे कम है। नकद-आरक्षित अनुपात (सी.आर. आर.) 50 आधार प्वाइंट कम करके। जून, 2002 से 5.0 प्रतिशत कर दिया गया और 16 नवम्बर, 2002 से आरम्भ पखवाड़े से और घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया गया। चालू वर्ष में पांच बड़े वाणिज्यिक बैंकों का पी.एल.आर. 11. 00-12.00 प्रतिशत से कम होकर 10.75-11.50 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष में एक उल्लेखनीय गतिविधि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उप-पी.एल.आर. ऋण देना है। सरकारी प्रतिभूतियों पर आय में कमी की प्रवृत्ति बनी रही। 7.4 प्रतिशत वाली 12 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों में आय 31 दिसम्बर, 2002 को कम होकर 6.13 प्रतिशत के स्तर पर थी।

1.13 वर्ष 2000-01 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनुत्पादक परिसंपत्तियां (एन.पी.ए.) 7,164 करोड़ रुपये बढ़कर 70,905 करोड़ रु. की हो गई जबकि निवल एन.पी.ए. 3,084 करोड़ रु. बढ़कर 35,546 करोड़ की हो गईं। वर्ष 2001-02 में वर्धमान सकल एन.पी.ए., जो वर्ष 2000-01 में राशि के दोगुने से अधिक हैं, मुख्यतया आई. सी.आई.सी.आई. का आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ विलयन के परिणामस्वरूप सकल एन.पी.ए. में 4,512 करोड़

रुपए की राशि शामिल किए जाने के कारण हैं। वसूलियों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एन.पी.ए. में वृद्धि हुई। विदेशी बैंकों के मामले में वसूलियां एन.पी.ए. में निवल संवृद्धि से अधिक थीं। अग्रिमों तथा कुल परिसम्पत्तियों के प्रति वाणिज्यिक बैंकों के सकल तथा निवल एन.पी.ए. के अनुपात सभी बैंक समूहों में कम हो रहे हैं। सकल अग्रिमों के 11.1 प्रतिशत तथा कुल परिसम्पत्तियों के 4.9 प्रतिशत पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सकल एन.पी. ए. निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों से अपेक्षाकृत उच्च हैं। प्राथमिकता-भिन्न क्षेत्रों को अग्रिम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (53.5 प्रतिशत) तथा निजी बैंकों (77.9 प्रतिशत) दोनों के मामले में बकाया एन.पी.ए. के बड़े भाग के लिए उत्तरदायी थे। मार्चांत, 2002 की स्थिति के अनुसार, 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) में से 25 का जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.) 9 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक था। इनमें से 23 बैंकों का सी.आर.ए.आर. 10 प्रतिशत से अधिक था। दो पी. एस. बी., दो निजी क्षेत्र के बैंक तथा एक विदेशी बैंक न्यूनतम सी.आर.ए.आर. की शर्त पूरी नहीं करते थे। समग्र रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सी.आर.ए.आर. मार्चांत, 2001 में 11.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्चांत, 2002 में 11.8 प्रतिशत हो गया।

1.14 पूंजी बाजारों में मंदी जारी रही। एन.एस.ई.-50 सूचकांक, जो जनवरी 2002 में 1,087 था, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न दर्शाते हुए जनवरी 2003 में 1,073 था। द्वितीयक बाजार में इस कमजोरी के कारण प्राथमिक बाजार में लघु प्रमात्रा में निर्गम हुए। तथापि, दिसम्बर, 2001 के पश्चात् की अवधि में भारतीय इक्विटी बाज़ार में गिरावट अनेक अन्य देशों से अपेक्षाकृत कम है। पूर्ववर्ती वर्षों में भारी अंतर्वाहों के विपरीत अप्रैल से नवम्बर, 2002 की अवधि में भारत से विदेशी पोर्टफालियो निवेश का थोड़ा सा बर्हिप्रवाह हुआ।

1.15 तथापि घरेलू पूंजी बाजारों में मंदी की दशाओं में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार छिपे हुए हैं। इक्विटी बाजार ने चल निपटान तथा इक्विटी व्युत्पाद व्यापार के साथ एक नवीन बाज़ार अभिकल्प समाहित किया है। नकदी, जिस पर जुलाई 2001 में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, सुधरकर मार्च, 2002 से सशक्त स्तर पर वापस आ गई है। वर्ष 2001 में लेनदेनों की संख्या के आधार पर दो भारतीय एक्सचेंजों राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) तथा मुम्बई स्टॉक एक्सचेज (बी.एस.ई.) का स्थान सम्पूर्ण विश्व के एक्सचेंजों में तीसरा तथा छठा था।

1.16 दूरभाष द्वारा लेनदेन किए गए बांडों तथा विदेशी मुद्रा के लिए क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि॰ (सीसीआईएल) द्वारा निष्पादित जोखिम प्रबंधन कार्यों ने निपटान जोखिम के संबंध में सुरक्षा का एक नवीन स्तर प्रदान किया है। जनवरी, 2003 में स्टॉक एक्सचेंजों में सरकारी बांडों का कारोबार शुरू हो गया जिससे सरकारी बांड बाज़ार के लिए पारदर्शिता तथा बाजार पहुंच का एक नया स्तर आरम्भ हुआ। यह द्विपक्षीय वार्ता से परे अज्ञात स्क्रीनाधारित आदेश तुलन की ओर एक स्वागतयोग्य कदम है।

1.17 सेबी अधिनियम में हाल में किए गए विधायी संशोधनों ने उचित बाजार आचरण के प्रवर्तन के लिए सेबी को बेहतर आधार प्रदान किया है। इससे बाजार कदाचार की सीमा को घटाने में सहायता मिलेगी तथा बाजार दक्षता में सुधार होगा। यू.टी.आई. को दो भागों — यू.टी.आई. -1 तथा यू.टी.आई-2 में विभाजित करने तथा यू.टी.आई.-2 को मालिकों के नवीन समूह को सौंपने के लिए यू.टी.आई. अधिनियम निरस्त किया गया।

1.18 केन्द्र तथा राज्यों दोनों में, सरकारी वित्त साधनों में, जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् वर्ष 1997-98 से दबावाधीन थे, वर्ष 2001-02 में और ह्रास हुआ। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा, जो वर्ष 1996-97 में 4.1 प्रतिशत से निरंतर बढ़ता हुआ वर्ष 2000-01 में 5.6 प्रतिशत हो गया था, वर्ष 2001-02 में और बढ़कर अनुमानत: 5.9 प्रतिशत पर पहुंच गया। केन्द्र सरकार का प्राथमिक घाटा (राज्यों के लघु बचत संग्रहणों के प्रति राज्यों को दिए गए ऋणों को निकाल कर) वर्ष 1996-97 में एक लघु अतिशेष का रूप लेने के बाद तत्पश्चात् ह्रासित होना शुरू हो गया और वर्ष 2001-02 में स.घ.उ. के 1.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। राज्य स्तर पर राजकोषीय समेकन का अभाव उनके संयुक्त राजकोषीय घाटे के समान रूप के ह्रास से उद्घाटित होता है, जो स.घ.उ. के अनुपात के रूप में वर्ष 1996-97 में 2.7 प्रतिशत से वर्ष 2000-01 में 4.3 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2001-02 में और ह्रासित होकर 4.7 प्रतिशत के संशोधित अनुमान स्तर पर पहुंच गया। केन्द्र तथा राज्यों का समेकित राजकोषीय घाटा वर्ष 2001-02 के संशोधित अनुमानों के अनुसार स.घ.उ. का 10.0 प्रतिशत था।

1.19 चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में केन्द्रीय वित्त साधनों ने पर्याप्त सुधार दर्शाया जब राजकोषीय घाटा 86,269 करोड़ रुपए था जो अप्रैल-दिसम्बर, 2001 में परिलक्षित 89,014 करोड़ रुपए के आंकड़े से थोड़ा सा कम था। तथापि, वर्ष की शेष अवधि में राजस्व तथा व्यय दोनों पर कुछ दवाब दिखाई दिए। अभिवृद्धि के संवेग के अप्रत्याशित रूप से कमजोर पड़ जाने से राजस्व संग्रहण प्रभावित हो सकते हैं। व्यय प्रबंधन भी उच्चतर फार्म समर्थन मूल्यों, संवर्धित प्रतिधारण मूल्यों से उच्चतर उर्वरक संबंधी आर्थिक राजसहायता, बाजार कीमतों से कम मूल्य पर द्रवित पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) तथा केरोसीन के वितरण के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक राजसहायता तथा सूखा राहत पर अप्रत्याशित व्यय के कारण अपेक्षाकृत अधिक चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। विनिवेश कार्यक्रम निर्धारित समय अनुसूची से पीछे चल रहा है तथा इस शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में कमी होने की संभावना है। वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार को यू.टी.आई. के पुनरुद्धार के लिए 938 करोड़ रुपए के बजटीय संसाधन उपलब्ध कराने पड़े।

1.20 राज्यों के स्तर पर, जबकि राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान तथा मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम जैसी अनेक पहलें की गई हैं, राजकोषीय मोर्चे पर दबाव जारी है। जबकि केन्द्र तथा राज्य, दोनों के व्यय संघटन ने वेतन, मजदूरी, ब्याज संदाय तथा आर्थिक राजसहायता की प्रबलता प्रतिबिम्बित करना जारी रखी है, हाल के महीनों में ब्याज दरों के उदार किए जाने से ब्याज संदाय मोर्चे पर कुछ स्वागतयोग्य राहत मिली है। उच्च राजकोषीय घाटे ने विपरीत चक्रीय राजकोषीय नीतियों को संचालित करने तथा अत्यावश्यक सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना पर परिव्ययों को बढ़ाने तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्य को जटिल बनाना जारी रखा है।

1.21 वर्ष 1997 में घोषित समयसूची के अनुसार 1 अप्रैल, 2002 से पैट्रोलियम में प्रशासित मूल्य तंत्र को समाप्त किया जाना चालू वर्ष में किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार था। चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में सुधारों ने गति पकड़ी। संसद के शीतकालीन सत्र में अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए जिनमें वित्तीय परिसम्पत्तियों और प्रतिभूतियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्संरचना विधेयक, 2002, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2002, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) विधेयक 2002, मनी लांड्रिंग की रोकथाम विधेयक, 2002 कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2002/कम्पनी (द्वितीय संशोधन), विधेयक 2002 तथा प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2001 शामिल हैं। निजीकरण संबंधी अनिश्चितता का समाधान भी भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि॰ के लिए विनिवेश नीति संबंधी घोषणा से दिसम्बर, 2002 में हो गया।

(ख) उपभोग, बचतें तथा निवेश

1.22 लड़खड़ाते वैश्विक सुधार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में सतत् अभिवृद्धि का प्रमुख घटक निजी अंतिम उपभोग व्यय रहा है। वर्ष 1993-94 की स्थिर कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय में स्थिर कीमतों पर घटक लागत पर स.घ.उ. में केवल 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2001-02 में 48,275 करोड़ रुपए अर्थात् 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 1.2)। बाजार कीमतों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में निजी अंतिम उपभोग व्यय–दोनों स्थिर कीमतों पर – वर्ष 2000-01 में 62.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 62.5 प्रतिशत हो गया।

1.23 वर्ष 2001-02 में निजी अंतिम उपभोग व्यय के संघटन ने अनेक वर्षों से परिलक्षित की जा रही प्रवृत्तियों में परिवर्तन प्रदर्शित किया। स्थिर कीमतों पर समग्र उपभोग में खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों तथा तम्बाकू का हिस्सा, जो वर्ष 1993-94 में 54.8 प्रतिशत से निरंतर घटता हुआ वर्ष 2000-01 में मात्र लगभग 48.1 प्रतिशत रह गया था, सुधर कर वर्ष 2001-02 में 48.8 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि अधिकांशत: अनाजों पर व्यय के हिस्से में एक प्रतिशतांक बिंदु से अधिक की वृद्धि के कारण थी। अनाज पर व्यय संभवत: खाद्यान्नों की खुली बाजार कीमतों पर दबावों के कारण बढ़ा जिन की आपूर्ति में केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारी अधिप्राप्ति के कारण कमी आई। उपभोग की अन्य प्रमुख श्रेणियों में, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर व्यय में 0.3 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई। कपड़ों तथा जूतों, सकल किराए, ईंधन तथा विद्युत और फर्नीचर, फर्निशिंग, उपस्करों तथा सेवाओं के हिस्से में गिरावट आई जबकि परिवहन एवं संचार तथा मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाओं का हिस्सा अपरिवर्तित रहा।

1.24 वर्ष 2001-02 में, बाजार कीमतों पर स.घ.उ. में अपने हिस्से का वर्धन करने के लिए चालू कीमतों पर सकल तथा निवल घरेलू बचतों में क्रमश: 11.8 प्रतिशत तथा 13.3

सारणी 1.2 : सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का संघटन

संघटक	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन									
	(वर्तमान मूल्यों पर)					(1993-94 मूल्यों पर)				
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01अ.	2001-02क्यू.	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01अ.	2001-02क्यू.
कुल अंतिम उपभोग व्यय	**10.0**	**17.3**	**12.5**	**6.6**	**10.1**	**3.8**	**7.4**	**7.1**	**2.3**	**6.1**
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	18.2	24.3	17.3	5.4	11.5	11.1	12.9	13.2	0.6	7.2
निजी अंतिम उपभोग व्यय	8.6	16.1	11.6	6.9	9.8	2.6	6.4	6.0	2.6	5.9
सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जिसमें से	11.8	5.0	24.3	3.3	8.0	7.7	0.7	20.3	-1.4	3.0
सकल नियत पूंजी निर्माण	6.0	13.3	11.4	9.6	9.6	2.1	8.7	9.3	3.8	3.2
वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	14.0	18.2	16.6	27.4	4.9	—	—	—	—	—
घटाइए - वस्तुओं और सेवाओं का आयात	14.5	21.9	18.2	15.2	4.6	—	—	—	—	—

क्यू : त्वरित अनुमान। अ: अनन्तिम
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

प्रतिशत की वृद्धि हुई। बाजार कीमतों पर स.घ.उ. (एनएनपी) के अनुपात के रूप में सकल (निवल) घरेलू बचतें वर्ष 2000-01 में 23.4 (15.4) प्रतिशत से सुधरकर वर्ष 2001-02 में 24.0 (16.0) प्रतिशत हो गईं (सारणी 1.3)। पारिवारिक क्षेत्रक एक बार फिर सर्वोत्तम निष्पादनकर्त्ता था जिसकी सकल बचतों में वृद्धि सकल घरेलू बचतों में कुल वृद्धि से अधिक थी। परिवारों ने अपनी कुल बचतों में वित्तीय बचतों का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 48.0 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2001-02 में 49.8 प्रतिशत कर दिया। निजी कार्पोरेट बचतों में हुई वृद्धि मोटे तौर पर पारिवारिक बचतों में वृद्धि की आधी दर पर थी। सार्वजनिक क्षेत्र न केवल एक निवल व्यय कर्त्ता बनना जारी रहा बल्कि इसने अपने व्यय में

सारणी 1.3 : बचत और निवेश

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (अ)	2001-02 (क्यू)
	(चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उतपाद के प्रतिशत के रूप में)						
सकल घरेलू बचतें	**25.1**	**23.2**	**23.1**	**21.5**	**24.1**	**23.4**	**24.0**
सरकारी	2.0	1.7	1.3	-1.0	-1.0	-2.3	-2.5
निजी	23.1	21.5	21.8	22.5	25.1	25.7	26.5
पारिवारिक	18.2	17.0	17.6	18.8	20.8	21.6	22.5
वित्तीय	8.9	10.4	9.6	10.5	10.7	10.4	11.2
वास्तविक	9.3	6.7	8.0	8.4	9.6	11.2	11.3
निजी कॉर्पोरेट	4.9	4.5	4.2	3.7	4.4	4.1	4.0
सकल घरेलू निवेश*	**26.9**	**24.5**	**24.6**	**22.6**	**25.2**	**24.0**	**23.7**
सरकारी	7.7	7.0	6.6	6.6	6.9	6.4	6.3
निजी	18.9	14.7	16.0	14.8	16.7	16.1	16.1
सकल घरेलू निवेश*	**26.9**	**24.5**	**24.6**	**22.6**	**25.2**	**24.0**	**23.7**
जी.एफ.सी.एफ.	24.4	22.8	21.7	21.5	21.8	21.8	21.7
स्टॉक में परिवर्तन	2.2	-1.0	0.9	-0.1	1.9	0.7	0.8
बचत-निवेश में अंतर@	**-1.7**	**-1.3**	**-1.5**	**-1.0**	**-1.1**	**-0.6**	**0.2**
सरकारी	-5.6	-5.4	-5.3	-7.6	-8.0	-8.7	-8.8
निजी	4.2	6.8	5.8	7.7	8.4	9.5	10.3

टिप्पणी : (i) सकल घरेलू निवेश सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) का द्योतक है।
(ii) आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवत: योग से मेल न खाएं।
* : भूल-चूक के लिए समायोजित
@ : बचत और निवेश की दरों के बीच अंतर का द्योतक है।
जी.एफ.सी.एफ. : सकल नियत पूंजी निर्माण
अ : अनन्तिम अनुमान; क्यू : त्वरित अनुमान
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

लगभग 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की। विभागीय उद्यम वर्ष 2001-02 में निवल व्ययकर्त्ता बन गए। गैर-विभागीय उद्यमों द्वारा वर्धित बचतें सरकारी प्रशासन के वर्धित निवल व्यय द्वारा पूर्ण से भी अधिक निष्प्रभावी हो गई।

1.25 स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण में वर्ष 2001-02 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो स.घ.उ. की अभिवृद्धि से अपेक्षाकृत काफी कम थी (सारणी 1.4)। वर्तमान कीमतों पर सकल पूंजी निर्माण वर्ष 2001-02 में स. घ.उ. का 23.7 प्रतिशत बना जो वर्ष 2000-01 में परिलक्षित 24.0 प्रतिशत तथा वर्ष 1999-2000 में परिलक्षित 25.2 प्रतिशत हिस्से से थोड़ा सा कम था। वर्ष 2001-02 में, सकल पूंजी निर्माण के संघटकों में से ऐसा प्रतीत होता है कि सकल नियत पूंजी निर्माण की अपेक्षा स्टॉक परिवर्तनों में कहीं अधिक तीव्र दर पर वृद्धि हुई। तथापि, नियत पूंजी निर्माण में, मशीनरी तथा उपकरण में सकल निवेश की अपेक्षा निर्माण में सापेक्ष रूप से तीव्र वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में, निर्माण में पूंजीनिर्माण 7.2 प्रतिशत की तीव्र दर से बढ़ा।

1.26 घरेलू मांग, और विशेष रूप से निजी अंतिम उपभोग व्यय हाल के वर्षों में वृद्धि को बढ़ावा देते रहे हैं (चित्र 1.2)। वर्ष 2000-01 में, निजी अंतिम उपभोग व्यय ने वर्तमान बाजार कीमतों पर स.घ.उ. में अभिवृद्धि में 73.6 प्रतिशत का योगदान दिया जो न केवल वर्ष 1999-2000 में अभिवृद्धि में 48.4 प्रतिशत के तदनुरूपी योगदान से पर्याप्त अधिक था, बल्कि अभिवृद्धि में विगत तीन वर्षों (वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-00) में 58.9 प्रतिशत के निजी अंतिम उपभोग व्यय के औसत योगदान से भी काफी अधिक था। अभिवृद्धि में निवेश का योगदान एक विषम पैटर्न का अनुसरण करता आ रहा है जिसमें एक वर्ष में पर्याप्त उच्च योगदान के बाद अगले वर्ष में अल्प योगदान हुआ है। यही विषम व्यवहार पुन: वर्ष 2001-02 में दृष्टि-गोचर हुआ जब निवेश स.घ.उ. में वृद्धि का लगभग 20 प्रतिशत थे। निवेश ने उपभोग व्यय द्वारा योगदान के हिस्से में गिरावट को पूरा किया जो फिर भी स.घ. उ. अभिवृद्धि में वृद्धि के पचास प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी होकर सबसे बड़ा एकल अंशदाता रहा।

सारणी 1.4 : वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (अ)	2001-02 (क्यू)
	(बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 1993-94 मूल्य)						
जी.डी.सी.एफ.*	**27.3**	**25.1**	**25.9**	**24.6**	**27.7**	**26.2**	**25.6**
सरकारी	7.6	6.8	6.5	6.6	7.0	6.4	6.2
निजी	19.3	15.5	17.3	16.7	19.0	18.3	18.0
निजी कार्पोरेट क्षेत्र	9.9	8.7	9.0	7.6	7.7	5.8	5.7
पारिवारिक क्षेत्र	9.4	6.9	8.3	9.1	11.3	12.4	12.3
जी.एफ.सी.एफ.	**24.7**	**23.4**	**22.9**	**23.4**	**23.9**	**23.9**	**23.4**
सरकारी	7.6	6.7	6.2	6.4	6.2	6.0	5.8
निजी	17.1	16.7	16.6	17.0	17.7	17.8	17.6
स्टाक में परिवर्तन	**2.2**	**-1.0**	**0.9**	**-0.1**	**2.0**	**0.7**	**0.8**
सरकारी	-0.0	0.2	0.3	0.1	0.8	0.3	0.4
निजी	2.2	-1.2	0.7	-0.3	1.2	0.4	0.4
			वृद्धि दर प्रतिशत में				
जी.डी.सी.एफ*	**11.1**	**-1.0**	**7.7**	**0.7**	**20.3**	**-1.4**	**3.0**
सरकारी	-6.5	-3.1	-0.8	7.3	13.3	-5.0	2.7
निजी	38.5	-13.7	16.4	2.6	21.5	0.0	4.2
जी.एफ.सी.एफ.	**19.3**	**1.5**	**2.1**	**8.7**	**9.3**	**3.8**	**3.2**
सरकारी	-6.5	-5.9	-2.8	9.4	2.7	2.0	0.7
निजी	36.1	4.8	4.1	8.4	11.8	4.5	4.1

टिप्पणी : जीडीसीएफ : सकल घरेलू पूंजी निर्माण; जीएफसीएफ : सकल नियत पूंजी निर्माण;
आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवत: योग से मेल न खाएं।
* : भूल-चूक के लिए समायोजित अ: अनन्तिम अनुमान; क्यू : त्वरित अनुमान
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

चित्र 1.2

चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. अभिवृद्धि में योगदान (1996-97 — 2001-02)

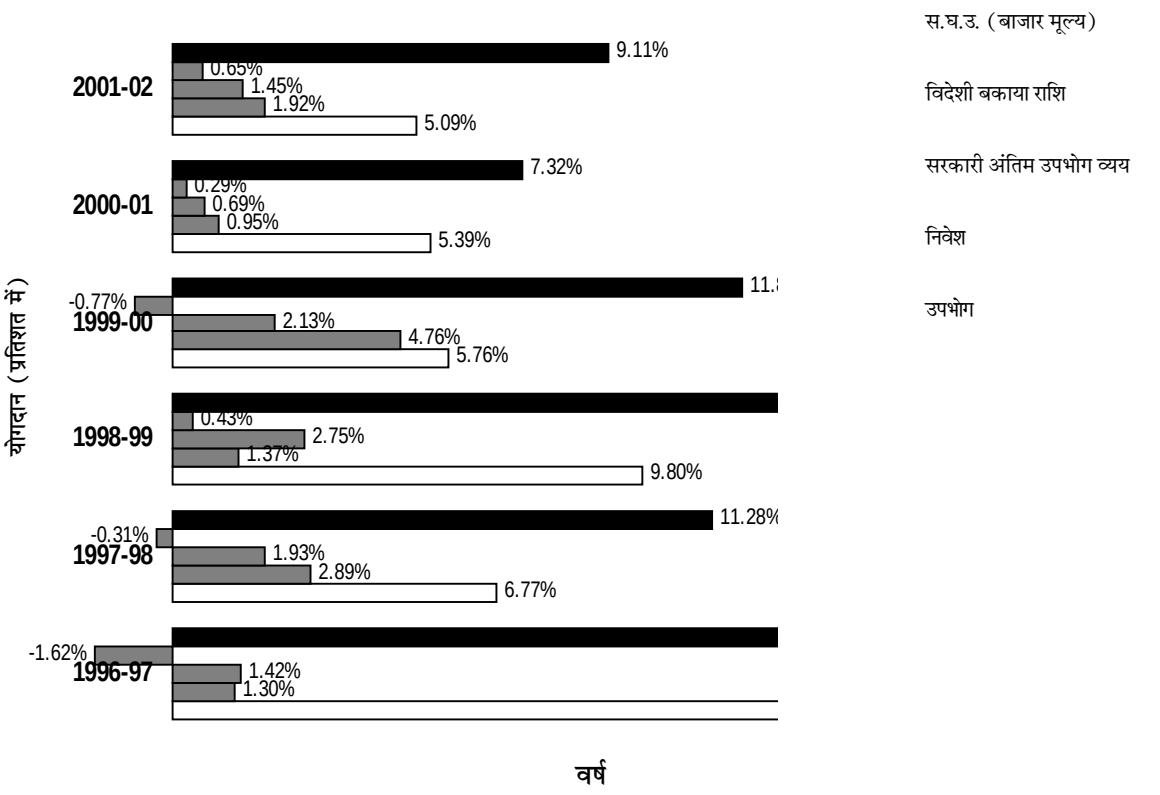

1.27 सार्वजनिक निवेश सरकारी उपभोग व्यय में वृद्धि से अंशत: निरूद्ध हुआ है जिसमें मजदूरी तथा वेतन, वस्तुओं तथा वर्तमान उपयोग के लिए सेवाओं पर व्यय शामिल है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात वेतन तथा मजदूरी में वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के कुल व्यय के अनुपात के रूप में, यह वर्ष 1990-91 में 22.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 23.6 प्रतिशत हो गया। यद्यपि कुल व्यय में वेतन तथा मजदूरी का हिस्सा वर्ष 1998-99 में 11.1 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2001-02 (सं.अ.) में 10.1 प्रतिशत हो गया, कुल व्यय में उपभोग व्यय का हिस्सा वर्ष 2000-01 से पुन: उर्ध्वगामी प्रवृत्ति निर्दिष्ट करता है। कुल केन्द्रीय व्यय में उपभोग व्यय का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 21.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 22.9 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2002-03 में इसके और बढ़कर 23.2 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। यह मुख्य रूप से वस्तुओं तथा वर्तमान उपयोग के लिए सेवाओं पर व्यय में वृद्धि के कारण है।

1.28 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यथा-समेकित राज्य सरकारों के उपभोग व्यय संबंधी जानकारी केवल वर्ष 1999-2000 तक ही उपलब्ध है। राज्य सरकारों के कुल व्यय में उपभोग व्यय का हिस्सा वर्ष 1997-98 में 38.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 39.6 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 1999-2000 में लगभग उसी स्तर पर बना रहा। कुल व्यय में मजदूरी तथा वेतन का हिस्सा वर्ष 1997-98 में 30.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 32.1 प्रतिशत हो गया।

1.29 सरकारी उपभोग व्यय के अतिरिक्त कुल व्यय में चालू अंतरणों के अनुपात में वृद्धियों के कारण सार्वजनिक निवेश में भी कमी आई है। ऐसे अंतरणों में, अन्यों के साथ, ब्याज संदाय, आर्थिक राजसहायता, पेंशन तथा अनुदान शामिल हैं। केन्द्र सरकार के कुल व्यय के अनुपात के रूप में चालू अंतरण 1990 के पूरे दशक के दौरान स्थिर गति से बढ़े। इसके परिणामस्वरूप, कुल व्यय में केन्द्र सरकार के चालू व्यय का हिस्सा, जो कि खपतकारी व चालू प्रकृति का है,

वर्ष 1990-91 में 68.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 (सं.अ.) में 79.4 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2002-03 में इसके मामूली रूप से गिरकर 79.3 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। चालू अंतरणों में ब्याज का हिस्सा जो वर्ष 2000-01 में 53.2 प्रतिशत बैठता था, वर्ष 2001-02 में क्रमिक रूप से गिरकर 51.5 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2002-03 में इसके 49.5 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। तथापि, चालू अंतरणों में सब्सिडियों के हिस्से में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2000-01 में 15.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 16.2 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2002-03 में इसके बढ़कर 18.4 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। हाल के वर्षों में उदार होती ब्याज दरों ने कुल व्यय में ब्याज संदायों के घटे हुए हिस्से के रूप में राजकोष को कुछ राहत पहुंचाई है। राज्य सरकार के कुल व्यय के अनुपात के रूप में चालू अंतरण वर्ष 1997-98 में 42.5 प्रतिशत से गिरकर 1999-2000 में 39.8 प्रतिशत हो गए हैं।

1.30 सांकेतिक ब्याज दरों के उदार होने के परिणामस्वरूप थोक मूल्य सामान्य सूचकांक के 52 सप्ताह के औसत पर आधारित पांच प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों की वास्तविक मूल उधार दर वर्ष 1997 में 9.6 प्रतिशत से मामूली रूप से गिरकर जनवरी, 2003 में 9.0 प्रतिशत पर आ गई। जबकि उदार ब्याज दरों ने राजकोषीय समेकन और वर्धित सार्वजनिक निवेश के लिए कुछ राजकोषीय स्थान बनाया है तथा आवास क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया है, ऐसी दरों के लाभ निवेशकों के मनोभावों में सुधार के साथ कुछ समय में उच्च निजी निवेश के अर्थों में पूर्णतया संभूत होने की संभावना है। घटिया आधारभूत ढ़ांचे की सुविधाओं के कारण निवेशकों के मनोभावों पर बुरा असर पड़ा है। आधारभूत ढ़ांचे, विशेषतया सड़क व दूरसंचार में निवेश में वर्धन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ सड़क क्षेत्र में अग्रणी बना है चालू वर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना है।

1.31 विगत वर्षों में विदेशी चालू खाता सुदृढ़ होता रहा है जिसने घरेलू सामान व सेवाओं के लिए अतिरिक्त मांग मुहैया कराई है। तेईस वर्ष के अंतराल के पश्चात वर्ष 2001-02 में चालू खाते में देखा गया आधिक्य, मूल्य के अर्थों में, शेष विश्व द्वारा भारत को आपूरित वस्तुओं व सेवाओं की तुलना में शेष विश्व को भारत द्वारा अधिक प्रमात्रा में आपूर्ति की गई वस्तुओं तथा सेवाओं को दर्शाता है। जबकि देश के पारंपरिक निर्यात वाहक, उदाहरणार्थ, रत्न तथा आभूषण, वस्त्र, इंजीनियरी सामान, रसायन और अयस्क तथा खनिजों में सुदृढ़ सुधार हुआ है, सेवाओं के निर्यात ने सकल निर्यात अभिवृद्धि को तीव्रतम बढ़ावा दिया है। आयातों की तुलना में निर्यात में प्रोत्कर्ष ने घरेलू औद्योगिक अभिवृद्धि को सशक्त प्रोत्साहन दिया है।

1.32 व्यापार के निवल अर्थ, जो निर्यात व आयात के मूल्यों में तुलनात्मक परिवर्तन मापते हैं, 1990 के दशक के दौरान 1.5 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि के साथ घटते बढ़ते रहे हैं। तथापि, निर्यात के लिए मंदित मूल्य और तेल की ऊंची कीमत के साथ वर्ष 1999-2000 से इनमें ह्रास हो रहा है; वर्ष 2000-01 में इनमें 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई और वर्ष 2001-02 में 2.4 प्रतिशत का और ह्रास हुआ। व्यापार के मूल्य अर्थों में ह्रास के बावजूद, निर्यात की आयात-क्रय शक्ति को मापते हुए व्यापार के आय अर्थों में वर्ष 1996-97 को छोड़कर, 1990 के दशक के दौरान प्रत्येक वर्ष में सुसंगत रूप से सुधार हुआ। औसत रूप में व्यापार के आय अर्थों में वार्षिक अभिवृद्धि 11.7 प्रतिशत हुई है, जो अशंत प्रमात्रा अर्थों में सुदृढ़ निर्यात अभिवृद्धि द्वारा अभिप्रेरित है। वर्ष 2000-01 और वर्ष 2001-02 में निर्यात प्रमात्रा क्रमश: 23.9 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत बढ़ने से इन दो वर्षों में निर्यात की आयात-क्रय शक्ति में क्रमश: 18.3 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) उत्पादन

1.33 सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का हिस्सा वर्ष 1980 में 36 प्रतिशत से 12.8 प्रतिशत बिन्दु बढ़कर वर्ष 2001 में 48.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1980 तथा वर्ष 2001 के बीच सेवाओं के हिस्से में यह वृद्धि उल्लेखनीय रूप से अनेक अन्य एशियाई देशों में सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं के हिस्से में तदनुरूपी वृद्धि के समान है (सारणी 1.5)। सारणी 1.5 में दिए गए कुछ चयनित देशों, इंडोनेशिया व मलेशिया के सिवाय, में सेवाओं के हिस्से में वृद्धिकारी प्रवृत्ति है जो काफी हद तक कृषि के हिस्से में तदनुरूपी गिरावट से संतुलित हुई है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद का औद्योगिक हिस्सा भारत में विशेष रूप से कम प्रतीत होता है। यह संभावना है कि त्वरित अभिवृद्धि और विकास से सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग के हिस्से में वृद्धि होगी। वर्ष 1994-95 से भारत के लिए स॰घ॰उ॰ में क्षेत्रवार वास्तविक अभिवृद्धि दर की असकलित रूपरेखा सारणी 1.6 में दी गई है।

1.34 कृषि और उद्योग का तुलनात्मक निष्पादन और अभिवृद्धि में उनका योगदान वर्ष 2001-02 और चालू वर्ष में बिल्कुल भिन्न रहने की संभावना है। वर्ष 2001-02 में स॰घ॰उ॰ की अभिवृद्धि में एक प्रतिशतांक से अधिक की वृद्धि का कारण कृषि द्वारा संतुलित निष्पादन (5.7 प्रतिशत) था। इसके विपरीत, वर्ष 2001-02 में उद्योग का रिकार्ड सापेक्षरूप से निराशाजनक रहा जब पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में सभी उद्योग समूहों में अपेक्षाकृत कम अभिवृद्धि दर्ज हुई।

1.35 अप्रैल-नवम्बर, 2002-03 में 5.3 प्रतिशत की आईआईपी अभिवृद्धि के साथ उद्योग ने एक महत्वपूर्ण पुनरूद्धार का अनुभव किया है। यह एक व्यापक आधार वाला सुधार रहा है जिसमें खनन तथा उत्खनन में 5.7 प्रतिशत, विनिर्माण में 5.4 प्रतिशत तथा बिजली में 4 प्रतिशत सुधार शामिल है। इस अभिवृद्धि की ओर अभिगम करने वाले दो प्रमुख तत्व थे पूंजीगत वस्तुएं, जिनमें 9.9 प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई तथा उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं, जिनमें 12.7 प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई।

सारणी 1.5 : कुछ चयनित एशियाई देशों में चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार हिस्से में घट-बढ़

(प्रतिशत में)

देश	कृषि			उद्योग			सेवाएं		
	1980	1990	2001	1980	1990	2001	1980	1990	2001
चीन	30.1	27.0	15.2	48.5	41.6	51.1	21.4	31.3	33.6
भारत #	38.1	31.0	24.7	25.9	29.3	26.4	36.0	39.7	48.8
इन्डोनेशिया	24.8	19.4	16.4	43.4	39.1	46.5	31.8	41.5	37.1
कोरिया	14.9	8.5	4.4	41.3	43.1	41.4	43.7	48.4	54.1
मलेशिया	...	15.2	8.4	...	42.2	49.6	...	42.6	41.9
पाकिस्तान#	29.6	26.0	25.0	25.0	25.2	23.0	45.5	48.8	52.0
फिलीपिन्स	25.1	21.9	15.1	38.8	34.5	31.6	36.1	43.6	53.3
थाइलैंड	23.2	12.5	8.6	28.7	37.2	42.1	48.1	50.3	49.3

भारत और पाकिस्तान के लिए आंकड़े चालू उपादान लागत पर स.घ.उ. पर आधारित है।

स्रोत : एडीबी, महत्वपूर्ण संकेतक 2002

सारणी 1.6 : स.घ.उ. में क्षेत्रक संबंधी वास्तविक वृद्धि दर (उपादान लागत पर)

मद	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन							
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अ)	2001-2002 (क्यू)	2002-2003 (अ.अ.)
I. कृषि तथा सहयोगी क्षेत्र	**-0.9**	**9.6**	**-2.4**	**6.2**	**0.3**	**–0.4**	**5.7**	**-3.1**
II. उद्योग	**11.6**	**7.1**	**4.3**	**3.7**	**4.8**	**6.6**	**3.3**	**6.1**
1. खनन और उत्खनन	5.9	0.5	9.8	2.8	3.3	2.4	1.0	4.8
2. विनिर्माण	14.9	9.7	1.5	2.7	4.0	7.3	3.4	6.1
3. बिजली, गैस और जलापूर्ति	6.8	5.4	7.9	7.0	5.2	5.0	4.3	5.2
4. निर्माण	6.2	2.1	10.2	6.2	8.0	6.9	3.7	7.1
III. सेवाएं	**10.5**	**7.2**	**9.8**	**8.4**	**10.1**	**5.6**	**6.8**	**7.1**
5. व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	13.3	7.8	7.8	7.7	8.5	6.9	8.7	7.8
6. वित्तीय, स्थावर संपदा तथा व्यापार सेवाएं	8.2	7.0	11.6	7.4	10.6	3.5	4.5	6.5
7. सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	7.9	6.3	11.7	10.4	12.2	5.6	5.6	6.4
IV. उपादान लागत पर कुल सकल घरेलू उत्पाद	**7.3**	**7.8**	**4.8**	**6.5**	**6.1**	**4.4**	**5.6**	**4.4**

अ.अ. : अग्रिम अनुमान क्यू. : त्वरित अनुमान अ. : अनन्तिम अनुमान

स्रोत : केंन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

1.36 औद्योगिक वृद्धि का पुनरूद्धार ढुलाई यातायात गतिविधियों में भी प्रतिबिम्बित होता है। प्रमुख पत्तनों पर संचालित कार्गो में चालू वर्ष (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2.4 प्रतिशत की तुलना में है। इसी अवधि के दौरान, रेलवे ढुलाई यातायात में विगत वर्ष मे 2.6 प्रतिशत की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हवाई पत्तनों में संचालित आयात तथा निर्यात कार्गो में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई जबकि यात्रियों की संख्या में अभिवृद्धि ने भी विगत वर्ष की अधोगामी प्रवृत्तियों को प्रतिवर्तित कर दिया।

1.37 पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अभिवृद्धि के साथ-साथ आयातों में अभिवृद्धि निवेश मांग के पुनः प्रवर्तन को सुझाती है। इसकी पुष्टि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों द्वारा होती है जहां वर्ष 2002 में अंर्तप्रवाह विगत वर्ष में 19,265 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 21,286 करोड़ रुपए हो गए।

1.38 चालू वर्ष में उल्लेखनीय पुनरूद्धार का अनुभव करने वाले दो उद्योग, इस्पात तथा सीमेंट हैं। विश्व में इस्पात की कीमतें दिसम्बर, 2001 से बढ़ीं। इस्पात एवं सीमेंट के लिए घरेलू मांग का अनुसमर्थन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तत्वावधान में किए जाने वाले राजमार्ग निर्माण ने किया, तथा आवास क्षेत्र की अभिवृद्धि को आवास वित्त तक सुगम पहुंच तथा अनुकूल कर व्यवस्था ने बढ़ावा दिया। प्रौद्योगिकी में सुधारों तथा लागत में कमियों ने भारत को इस्पात एवं सीमेंट का निर्यात करने में अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया। इन कारणों से वर्ष 2001-02 में इस्पात उत्पादन में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा अप्रैल-नवम्बर, 2002 में 24.5 प्रतिशत की और अभिवृद्धि हुई। वर्ष 2002-03 के पूर्वार्ध में सीमेंट उत्पादन में 9.5 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई।

1.39 कपड़ा उद्योग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां भारत को श्रम गहन निर्यातों का अवसर प्राप्त है। कपड़ा उत्पादों ने अप्रैल-नवम्बर, 2002 में 14.8 प्रतिशत की सशक्त अभिवृद्धि दर्शाई। इस का एक घटक डालर के रूप में तैयार-निर्मित परिधानों के निर्यातों में 11.6 प्रतिशत की अभिवृद्धि था। वस्त्रों में अधिकांश वृद्धि पावरलूम खंड के कारण थी।

1.40 पर्यटन एक पर्यावरण अनुकूल, श्रम गहन, निर्यातोन्मुखी क्षेत्रक है। संयुक्त राज्य अमरीका में 11 सितम्बर, 2001 के आक्रमण तथा अन्य घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप भारत में पर्यटकों के आगमन में भारी कमी आई। अनेक विदेशी सरकारों द्वारा यात्रा परामर्श दिए गए जिनमें उन्होंने अपने राष्ट्रिकों को भारत की यात्रा न करने का परामर्श दिया। इसके परिणामस्वरूप समूह रद्दीकरण तथा सीमित भावी बुकिंग हुई। अक्तूबर, 2002 से पुनः प्रवर्तन के चिन्ह दर्शित हुए हैं।

1.41 निम्न ब्याज दरों, उपभोक्ता वित्त में अभिवृद्धि तथा सशक्त निर्यात मांग से सहायता पाकर आटोमाबाईल उद्योग में सुदृढ़ वृद्धि हो रही है। अप्रैल-दिसम्बर 2002-03 के दौरान निर्यात किए गए वाहनों की संख्या तदनुरूपी विगत अवधि में 1,28,119 की तुलना में 2,15,318 थी जो 68 प्रतिशत की उत्प्लावक वृद्धि है। इस उद्योग में अधिकांश प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के अब भारत में प्रचालन हैं तथा वे निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए मंच के रूप में भारत का वर्धनात्मक प्रयोग कर रही हैं। आटोमोबाईल उद्योग के सभी पहलू भारत में सुदृढ़ रूप से कार्य कर रहे हैं जिनमें संघटकों से ले कर विभिन्न प्रकार के वाहन, अभिकल्प, अनुसंधान तथा परामर्श की परिष्कृत निविष्टियां शामिल हैं।

1.42 रत्न तथा आभूषणों, जिनका वर्ष 1998-99 से देश के कुल निर्यातों में 16-20 प्रतिशत हिस्सा रहा है, ने अप्रैल-अक्तूबर, 2001 में 12.2 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 2002 में 28.6 प्रतिशत की उत्प्लावक वृद्धि दर्ज की। निर्यातों में बढ़ोतरी मुख्यतया संयुक्त राज्य अमरीका को ब्रिक्री में उछाल को प्रतिबिम्बित करती है जो भारत के रत्न तथा आभूषणों का सबसे बड़ा आयातकर्ता है। इस का अनुसमर्थन सरकार की नीतिगत पहलों ने किया है यथा अपरिष्कृत हीरों के आयात को लाइसेंस-मुक्त करना। देश में कीमती रत्नों के लिए पूर्वेक्षण में नए प्रयास किए जा रहे हैं।

1.43 तेल और गैस उद्योग में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम नए ब्लॉकों में गैस का पता लगाना है। कृष्णा-गोदावरी अपतट में, तथा राजस्थान ब्लॉक में हाल की खोज के आरम्भिक अनुमानों के अनुसार तेल तथा तेल समकक्ष गैस के लगभग 220 मिलियन मीट्रिक टन के इन प्लेस रिजर्व हैं। वर्ष 2000-01 के उतरार्द्ध में, घरेलू मांग की तुलना में भारत में पर्याप्त परिशोधन क्षमता थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने निवल रूप में वर्ष 2001-02 में 3.08 मिलि. टन और अप्रैल-अक्तूबर, 2002 में 2.08 मिलि. टन पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया। इसके अतिरिक्त, तीन नए परिशोधन कारखाने

निर्माणाधीन हैं जिन से क्षमता 24 मिलि. टन बढ़ जाएगी। चालू वर्ष (अप्रैल–नवम्बर, 2002) के दौरान प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ कर 20.61 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) हो गया जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक था। देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सीबीएम नीति के तहत पहले दौर में 8 कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लॉक प्रदान किए गए हैं।

1.44 भारत इलैक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में निर्यातोन्मुखी उत्पादन में निरंतर प्रगति कर रहा है। पिछले पाँच वर्षों से सॉफ्टवेयर निर्यात 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की चक्रवृद्धि दर पर बढ़े है। हार्डवेयर निर्यात में भी प्रगति के चिन्ह अब दिखाई देने लगे हैं। हार्डवेयर निर्यात वर्ष 2000–01 और वर्ष 2001–02 में तेजी से बढ़ कर पिछले वर्ष की तुलना में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि सहित वर्ष 2001–02 में 5871 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए। पूरे विश्व से कई शीर्षस्थ सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों (आईटी) ने अपनी भूमंडलीय उत्पादन श्रृंखलाओं में और अनुसंधान एवं विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यो के लिए भारत का उपयोग करना आरंभ कर दिया है।

1.45 एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां नीति का संकेन्द्रण है, वह है असफलता का समाधान अथवा द्रुतगामी और कार्यकुशल तंत्रों का सृजन जिनके जरिए असफल फर्मों के श्रम और पूंजी का यथासंभव कार्य–कुशलता से पुन: उपयोग किया जा सकता है। यह ऋणदाताओं के अधिकारों की समस्या से निकटता से जुड़ा है। किसी ऋण के बकाया होने पर ऋणदाताओं को उगाही, कुर्क करने की क्षमता प्रदान करते हुए संसद में पारित वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा इन्फोर्समेंट आफ सिक्यूरिटी इंटेरस्ट विधेयक, 2002, तथा दिसम्बर, 2002 में कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधन जिन से बीआईएफआर के कार्यकरण में सुधार होने की आशा है। इन पहलों से असफल फर्मों के साथ जुड़े उत्पादन की हानि में महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना है। दिसम्बर, 2002 में संसद में प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2001 पारित किया गया। यह प्रतिस्पर्धा–समर्थक कानूनी ढांचा स्थापित करने, यह प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहारों तथा प्रभुत्व के दुरूपयोग को नियंत्रित करने और बाजारों के बेहतर विनियमन करने का प्रयास है।

1.46 सरकार ने अधिक उत्पादकता की खोज में गैर–केन्द्रीय उद्यमों का निजीकरण करने की नीति का अनुसरण किया है। सौदों का एक नियमित प्रवाह हुआ है, जहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या होटल जैसी उत्पादक परिसम्पत्तियां सामरिक बिक्री के जरिए बेची गई है। पहले व्यक्त की गई आशंकाओं के विपरीत इन सौदों से रोजगार पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े हैं।

1.47 वर्ष 2002–03 में, मौसमी वर्षा के सामान्य मात्रा से लगभग 19 प्रतिशत कम होने से देश ने वर्ष 1987–88 के बाद के सर्वाधिक अल्प मानसून का अनुभव किया। देश के सत्रह राज्यों को सामान्य से गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन (चावल, मोटा अनाज और दालें) में 19 प्रतिशत की गिरावट आई। वाणिज्यिक फसलों में तिलहन को सर्वाधिक हानि पहुंची, इसके बाद कपास और गन्ने का नम्बर था। जहां अप्रैल, 2002 में रबी की समृद्ध फसल ने चालू वर्ष की पहली तिमाही में कृषि में चार प्रतिशत की वृद्धि की, वहीं तदनंतर कम मानसून ने इस वर्ष की रबी फसल के उत्पादन पर प्रभाव डाला, हालांकि जनवरी–अंत की बारिश से पंजाब और हरियाणा में गेहूं की सामान्य फसल होने का आभास है।

1.48 पिछले वर्ष 212 मिलि. टन के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन कम होकर 183.2 मिलियन टन था, यह गिरावट (13.6 प्रतिशत गिरावट) बहुत अधिक है। तथापि, भाग्यवश खाद्यान्नों के संचित सरकारी भंडार ने इस गिरावट के लिए क्षतिपूर्ति से ज्यादा राहत पहुंचाई, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि प्राथमिक उत्पाद मूल्यों के मध्य मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव अनुपस्थित था।

1.49 हाल के समय में सर्वाधिक सुसंगत निष्पादक, सेवा क्षेत्र ने वर्ष 2001–02 तथा चालू वर्ष के पूर्वार्ध में भी अपनी संवृद्धि का संवेग बनाए रखा 1 वर्ष 2000–01 की तुलना में वर्ष 2001–02 में व्यापार, होटल और रेस्तरां और वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यापार सेवाओं ने अपने निष्पादन में सुधार किया। चालू वर्ष, में वर्षानुवर्ष आधार पर स.घ.उ. के रूप में सेवा क्षेत्र में पहली और दूसरी तिमाही में प्रत्येक में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र स. घ.उ. में वर्ष 2002–03 में 7.1 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2001–02 में अवलोकित 6.8 प्रतिशत की तुलना में एक उच्चतर दर है।

1.50 भौतिक बुनियादी ढांचे में वर्धित सरकारी निवेश द्वारा उत्पन्न मांग औद्योगिक सुधार के पीछे एक मुख्य प्रेरक रहा है। विश्व में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) की प्रभावशाली प्रगति ने इस्पात और सीमेंट उद्योगों के लिए सुदृढ़ पश्चगामी सम्पर्क उपलब्ध कराए हैं। चालू वर्ष में दूर-संचार में भी प्रमुख उपलब्धियां हासिल की गई हैं। चालू वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें से 63 प्रतिशत सेलुलर फोनों के कारण हैं, जो नए उपभोक्ताओं की मोबाइल सेवाओं के प्रति बढ़ती हुई प्राथमिकता को रेखांकित करती है। क्रमिक रूप से गिरते हुए प्रशुल्कों के कारण देश में सेलुलर अभिदाता आधार 5 वर्ष से कुछ अधिक समय के भीतर ही केवल 0.3 मिलियन से बढ़कर 10.4 मिलियन हो गया है।

1.51 अत्यंत अपर्याप्त वर्षा के कारण पनबिजली विद्युत द्वारा एक निराशाजनक निष्पादन के बावजूद, थर्मल और न्यूक्लियर उत्पादन में अच्छी वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान समग्र विद्युत उत्पादन में सुधार हुआ है। दस राज्यों द्वारा शत प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण प्राप्त करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण ने तेजी से प्रगति की है। देश वर्ष 2007 तक सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिए कटिबद्ध है। विद्युतीकरण के अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के जरिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिसके तहत 10,000 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें पहले ही निर्मित की जा चुकी हैं।

(घ) रोजगार और गरीबी

1.52 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 55वें दौर के वर्ष 1999-2000, के बाद से गरीबी के अनुमान के कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वर्ष 2000-01 के लिए भारत में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय और रोजगार बेरोजगारी की स्थिति पर एनएसएसओ के 56वें दौर (जुलाई, 2000-जून, 2001) की रिपोर्ट, यद्यपि कम अनुमानों पर आधारित है, श्रम बाजारों के घटनाक्रमों और मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर कुछ जानकारी उपलब्ध कराती है।

1.53 कार्य बल भागीदारी दर (डब्ल्यूएफपीआर) जो प्रति 1000 व्यक्ति नियोजित व्यक्तियों की संख्या है, पर 55वें दौर (जुलाई, 1999-जून, 2000) में सामान्य प्रास्थिति, के अनुसार जब केवल मूल प्रास्थिति पर विचार किया जाए, ग्रामीण (शहरी) पुरुषों के लिए 522 (513) से बढ़कर 56वें दौर में 532 (525) हो गई तथा मूल एवं सहायक (समस्त) प्रकार से विचार किए जाने पर 531 (518) से 544 (531) हो गई। चालू साप्ताहिक स्थिति के अनुसार ग्रामीण (शहरी) पुरुषों के लिए तदनुरूपी वृद्धि 510 (509) से बढ़ कर 525 (519) हो गई। तथापि, केवल मूल प्रास्थिति पर विचार किए जाने पर ग्रामीण (शहरी) महिलाओं के लिए डब्ल्यूएफपीआर के 55वें दौर (जुलाई 1999-जून 2000) में 231 (117) से गिरकर 56वें दौर में 221 (116) हो गई। जब मूल तथा सहायक दोनों स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है तो महिला डब्ल्यूएफजीआर दोनों दौरों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 299 से कम होकर 287 हो गई लेकिन शहरी क्षेत्रों में 139 से 140 की मामूली वृद्धि हुई है। चालू साप्ताहिक प्रास्थिति के अनुसार महिलाओं के लिए डब्ल्यूएफपीआर ग्रामीण क्षेत्र में 253 से गिरकर 217 और शहरी क्षेत्रों में 128 से गिरकर 117 हो गयी।

1.54 15-59 वर्ष की आयु समूह में ग्रामीण पुरुषों (सामान्य प्रास्थिति-समस्त) के लिए डब्ल्यूएफपीआर 55वें और 56वें दौर में 87 प्रतिशत थी। ग्रामीण महिलाओं के लिए डब्ल्यूएफपीआर 54वें दौर में 48 प्रतिशत से गिर कर 56वें दौर में 46 प्रतिशत हो गई है। इस अवधि के दौरान शहरी पुरुषों के लिए डब्ल्यूएफपीआर 78 प्रतिशत से बढ़ कर 79 प्रतिशत हो गयी। तथापि, शहरी महिलाओं के लिए, दोनों दौरों में डब्ल्यूएफपीआर लगभग 21 प्रतिशत थी। वर्ष 1998 से 2001 की अवधि के दौरान, 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लिए डब्ल्यूएफपीआर तीन श्रेणियों अर्थात् ग्रामीण पुरुषों, शहरी पुरुषों और शहरी महिलाओं के लिए वृद्धि की ओर अभिमुख है। शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए अधिक थी।

1.55 ग्रामीण भारत में 'सामान्य प्रास्थिति' के अनुसार लगभग 69 प्रतिशत पुरुष श्रमिक और 82 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं। शहरी भारत में, लगभग 58 प्रतिशत पुरुष श्रमिक और लगभग 48 प्रतिशत महिला श्रमिक तृतीयक क्षेत्रक गतिविधियों में संलग्न हैं।

1.56 55वें दौर से 56वें दौर के बीच, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के लिए अखिल भारत औसत ग्रामीण क्षेत्रों में 486.16 रु. से बढ़ कर 494.90 रु. और शहरी क्षेत्रों में 854.92 रु. से बढ़ कर 914.57 रु. हो गया।

1.57 संगठित क्षेत्र रोजगार में निजी क्षेत्र में कुछ सकारात्मक प्रवृति दिखाई दी है जो औद्योगिक क्षेत्र में उत्प्लावकता की जारी स्थिति में और अधिक बढ़नी चाहिए यदि श्रम कानूनों में कुछ अनम्यताओं को कम कर दिया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, संविदा श्रम अधिनियम, 1970 और मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 कुछ ऐसी कानूनी लिखतें है जिनमें सरकार संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक विधान लाने पर भी विचार कर रही है। जनवरी, 2002 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत खनन और निर्माण क्षेत्रों में केन्द्रीय परिधि में अनुसूचित रोजगार के संबंध में श्रमिकों के लिए मजदूरी में वृद्धि की गई।

1.58 एनएसएसओ दौरों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 1999 से जून, 2000 और जुलाई, 2000 से जून, 2001 के बीच, 1000 परिवारों में से हमेशा भुखमरी का सामना करने वाले (वर्ष के कुछ महीनों में भी प्रतिदिन पर्याप्त भोजन न पाने वाले) परिवारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से कम होकर 6 और शहरी क्षेत्रों में 7 से कम होकर 2 हो गई। ''मौसमी तौर पर भुखमरी'' का सामना करने वाले (वर्ष के केवल कुछ महीनों में प्रतिदिन पर्याप्त भोजन पाने वाले) परिवारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार परिवार 26 से कम होकर 19 और शहरी क्षेत्रों में 6 से कम होकर 4 रह गई। लगातार 'मौसमी भुखमरी' के इस साक्ष्य के विपरीत इस वर्ष के सूखे ने निरंतर कमी वाले अनेक क्षेत्रों की विपत्ति को बढ़ा दिया है। सूखे द्वारा देश के वृहत भागों के प्रभावित होने से एक सक्रिय खाद्य प्रबंधन नीति के अनुसरण से गरीबी और वंचन को नियंत्रित करने में सहायता मिली है। अन्नपूर्णा, विश्व खाद्य कार्यक्रम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दरिद्र लोग, पोषाहार कार्यक्रम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए होस्टल, काम के बदले अनाज और दोपहर का भोजन जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का उठाव अप्रैल-अक्तूबर, 2002 के दौरान 5.48 मिलियन टन पर पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 3.15 मिलि. टन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। पर्याप्त बफर स्टॉक के प्रबंधन के जरिए खाद्य सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता से गरीब वर्ग को कुछ ऐसी तकलीफों से बचाने में मदद मिली है जो इस देश में सूखे के साथ पारम्परिक रूप से जुड़ी हैं।

1.59 सूखे से राहत के अलावा, सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने के लिए कुछ अन्य उपाय किए हैं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसजी) के तहत केन्द्रीय आवंटन बढ़ाया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि से ऋणों पर ब्याज दर में कमी करने के साथ चालू वर्ष में निधि (आरआईडीएफ) की संचित राशि को भी बढ़ाया गया है। चल रही इंदिरा ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण आवास पहल को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यतया आवास वित्त के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों को बढ़ावा देने के कारण जैसाकि चालू वर्ष में आवास ऋण के उच्च बहिर्प्रवाह में परिलक्षित होता है, समग्र रूप से पूरे देश में आवासीय गतिविधि में वृद्धि के स्पष्ट चिन्ह प्रदर्शित हुए हैं। आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) आवास वित्त को बढ़ाने में मुख्य कर्ता रहा है। हुडको शहरी क्षेत्रों में कम लागत की जल मल योजना के कार्यान्वयन में भी सहायक रहा है जो मानवीय रूप से सफाई करने के कार्य को समाप्त करने की ओर अभिप्रेरित है और जिसके तहत दिसम्बर, 2002 के अंत तक लगभग 1500 शहरों में 860 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

मुद्दे और प्राथमिकताएं

1.60 जारी वर्ष दसवीं पंच वर्षीय योजना (2002-07) का प्रथम वर्ष है जिसमें 8 प्रतिशत की एक औसत वार्षिक वृद्धि दर परिकल्पित की गई है। हालांकि हाल के वर्षों का वृद्धि निष्पादन इस लक्ष्य से कम रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य तथा भारत का अपना अनुभव दर्शाते हैं कि लक्ष्य निश्चय ही सुगम है। पूर्वी-एशियाई संकट के आरंभ होने से पहले अनेक वर्षों तक अन्य पूर्वी एशियाई देशों के मध्य मलेशिया, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड की संपोषित वार्षिक वृद्धि दरें उस स्तर के समान या उससे अधिक रहीं हैं जो भारत दसवीं योजना में पाना चाहता है। चीन जनवादी गणराज्य जो कि क्षेत्र और जनसंख्या में भारत के समान ही एक विशाल देश है, 1980 और 1990 के दशक के दौरान विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मध्य सर्वोत्तम निष्पादनकर्त्ताओं में से एक रहा है और भूमंडलीय आर्थिक गतिविधि में हाल की मंदी के बावजूद उसने उच्च वृद्धि (7 प्रतिशत से ज्यादा) को बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त इन देशों में स्पष्ट रूप से अल्प प्रारंभिक स्तरों से वृद्धि में तेजी अत्यधिक तीव्रता लगभग छलांग लगाने के तरीके से आई है।

1.61 वृद्धि में तेजी के संबंध में भारत का अनुभव भी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के समान ही रहा है। 1950, 1960 और 1970 के दशकों में लगभग 3½ प्रतिशत के आसपास रहने के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था की दशकीय औसत वार्षिक वृद्धि दर 1980 के दशक में प्रमात्रात्मक उछाल ले कर 5.65 प्रतिशत पर पहुंच गई (चित्र 1.3)। इसी प्रकार, भुगतान संतुलन संकट के परिणामस्वरूप वर्ष 1991-92 में 1.3 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंचने के बाद वर्षिक वृद्धि दर तेजी से त्वरित होकर 1994-95 से 1996-97 के दौरान लगभग 7½ प्रतिशत पर पहुंच गई (चित्र 1.4)

1.62 सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के लिए बैंचमार्कों सहित, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा परिवर्तन और तीव्र अभिवृद्धि त्वरण के चालक होने चाहिए। अब भारत इन सभी तीनों कारकों का लाभ उठा रहा है। प्रौद्योगिकी का तेजी से उन्नयन हो रहा है तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रबल हो गई है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना उपलब्ध कराने और कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विभाजन को समाप्त करने के लिए देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति और समुत्थानशील सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। आयातों पर प्रमात्रात्मक प्रतिबंध अब विगत की बात होने, सीमाशुल्क क्रमिक रूप से कम होने और विदेशी निवेश-प्रत्यक्ष और पोर्टफालियो-दोनों को उदार बनाए जाने से, भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में भारत का एकीकरण भी प्रगति पर है। उत्प्लावक निर्यात निष्पादन जो चालू लेखे का एक अधिशेष है और सुदृढ़ भुगतान संतुलन स्थिति इस एकीकरण प्रक्रिया में देश की सफलता का प्रदर्शन करती है।

1.63 पूर्व में उल्लिखित परिवर्तन के चालकों के मध्य एक घनिष्ठ और सद्भावपूर्ण अन्योन्यक्रिया है। यह देश में उपभोक्ता वस्तुओं, आटोमाबाइल्स और दूरसंचार उद्योग द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया जा सकता है। पूर्व के प्रमात्रात्मक प्रतिबंधों के बाद अब उपभोक्ता वस्तुएं सीमा शुल्क का भुगतान करने पर मुक्त रूप से आयातित की जा सकती हैं। जहां कुछ विदेशी उपभोक्ता उत्पाद निश्चित रूप से दुकानों में दिखाई देने लगे हैं, विशेष रूप से अप-मार्केट खंडों में, उनकी विद्यमानता सीमित है। तथापि सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समाभिरूपता के कारण घरेलू उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

1.64 विगत में एक कठोर लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाला आटोमाबाइल क्षेत्र नई उदार व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष लाभानुभोगी रहा है। आटोमोबाइल का उत्पादन न केवल द्विअंकीय चक्रवद्धि दरों पर बढ़ा है बल्कि यह क्षेत्र एक वृहत निर्यातक बन गया है। प्रमुख

चित्र 1.3

भारत : दशकीय वृद्धि दरें (1951-52 — 1990-91)

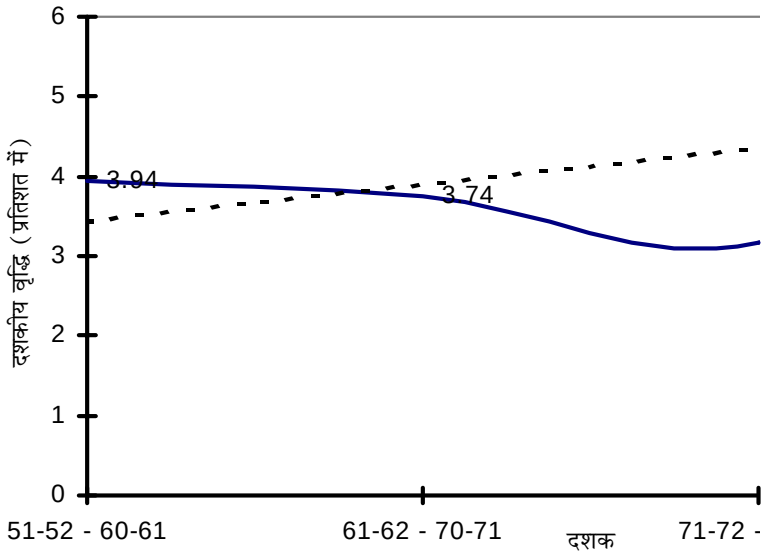

चित्र 1.4

भारत : वार्षिक स.घ.उ. वृद्धि (1991-92 — 1996-97)

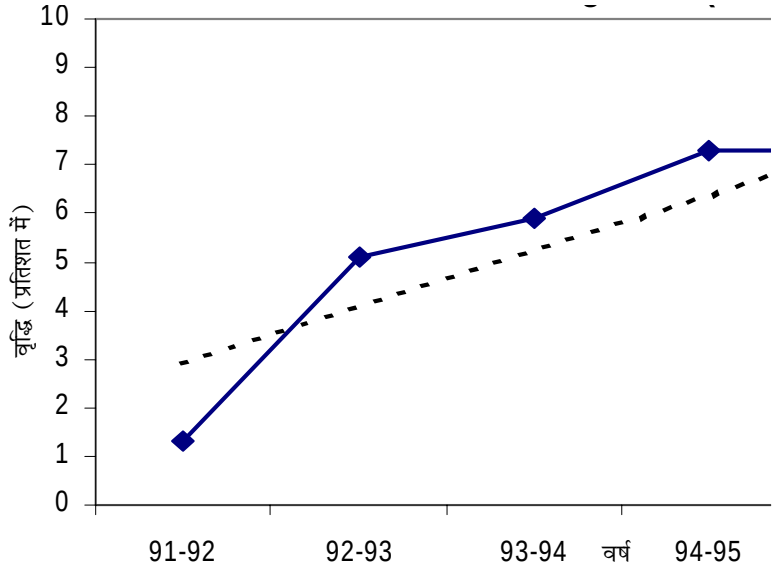

अंतर्राष्ट्रीय आटोमोबाइल कम्पनियां अब भारत में प्रचालन कर रही हैं और निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए देश का प्लेटफार्म के रूप में वर्धनात्मक प्रयोग कर रही हैं। अपस्ट्रीम फर्मों का एक सुदृढ़ समूह उनके लिए सहायक वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और आटोमोबाइल उद्योग को अभिकल्प परामर्श उपलब्ध करा रहा है। दूर-संचार क्षेत्र प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा के बीच सही अन्योन्यक्रिया का एक अन्य उदाहरण है। जहां मोबाइल टेलीफोनी तीव्रता से टेलीघनत्व को बढ़ा रही है, ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल (जीएसएम) और कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) नाम की दो प्रौद्योगिकियों के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा ने उपभोक्ता को मूल्य लाभ पहुंचाया है।

1.65 यह महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए बैंचमार्किंग के बीच इस सही अन्योन्यक्रिया का विस्तार कृषि तक भी किया जाए। जहां अनाजों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक रही है, वहीं कृषि में विविधता को बढ़ाने की प्रवृति को तीव्र करने की आवश्यकता है।

1.66 पिछले पांच दशकों में आबादी की वृद्धि के अनुरूप खाद्यान्नों की वृद्धि बनाये रखने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। भारत को इसमें सफलता मिली है। अभी तक कृषि नीति के सभी पहलुओं को कमी पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है क्योंकि खाद्यान्नों और चीनी जैसी अनिवार्य वस्तुओं की तीव्र कमियों को पूरा करने के लिए आयातों पर निर्भर रहना भारत जैसे बड़े देश के लिये जोखिमपूर्ण समझा गया। फिर भी अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र बचे हैं जो इस प्रक्रिया में अपेक्षतया उपेक्षित रहे हैं। भारत की सफलता संयुक्त राज्य अमरीका के बाद सबसे बड़े कृषि योग्य भूमि क्षेत्र की परिसंपत्तियों और विश्व में सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने के स्वामित्व में निहित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में अनेक कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं जिनके कारण यहां ऊष्ण कटिबंधीय, अर्ध ऊष्ण-कटिबंधीय एवं शीतोष्ण सभी प्रकार के उत्पादों का उत्पादन संभव है। अत: बागवानी उत्पादों में उत्पादकता सुधारों की दिशा में बढ़ने की ओर ध्यान दिया गया है जिनके अंतर्गत अनेक किस्मों के फल एवं सब्जियां शामिल हैं जिन्हें विश्व बाजार में तभी स्थान मिलेगाा जब ये उत्पाद उचित ग्रेड, उचित प्रसंस्करण, पैकेजिंग के हों और तीव्र एवं आधुनिक प्रेषण प्रणाली के अंतर्गत इनका परिवहन किया जाये। बागवानी, पुष्प-कृषि और रेशम उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण में मूल्य-वर्धन किसानों को अच्छा लाभांश दे सकता है और अच्छे रोजगार का क्षेत्र बढ़ सकता है। जहां महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और यहां तक कि उत्तर प्रदेश से भी फूलों एवं फलों के निर्यात के लिए विश्व बाजार में प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता की सूचनायें मिली हैं वहां मूल्य वर्धित बागवानी उत्पादों के

निर्यात के लिए भारी क्षमता तभी प्राप्त की जा सकती है जब प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद निर्यातों के अनुरूप समुचित आधार सुविधा देश में उपलब्ध हो। शीघ्र भेजे जाने वाले उत्पादों के लिये अनेक पत्तनों में यांत्रिकी लदान सुविधायें उपलब्ध नहीं है। इस समय भारत 145 मिलियन टन फलों एवं सब्जियों का उत्पादन करता है जिसमें से केवल 2 प्रतिशत से कम हिस्सा प्रसंस्करण मार्ग से जाता है जिससे भारतीय उत्पादक मूल्य वर्धन एवं विश्व बाजारों तक पहुंच के लाभों से वंचित रह जाते हैं।

1.67 इसके अलावा जो आवश्यक है वह केवल उन्नत बीज प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक सिंचाई प्रणालियां ही नहीं है बल्कि ऐसे विशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग भी आवश्यक हैं जो विभिन्न कृषि उत्पादों के अनुकूल हों। अनाज तथा तिलहनों से भिन्न फल तथा सब्जियां खराब होने वाली वस्तुएं हैं। उनके परिरक्षण के लिए शीत भंडार आवश्यक हैं। शीत-भंडारों के विस्तार में इस वर्ष कुछ तेजी आई है परन्तु अनियमित एवं घटिया किस्म की विद्युत आपूर्ति शीत भंडारणों की वृद्धि के लिये गंभीर रूकावट के रूप में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मूल्यवर्धन और इससे होने वाली आय एवं रोजगार वृद्धि अपेक्षित आधार संरचना के निर्माण पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। इस आधार संरचना को बढ़ाने में सरकारी-निजी भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। पहले सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया था जिसका अधिक उत्साह के साथ नवीकरण करना होगा विशेषकर जल-संभरण विकास के माध्यम से! पीने योग्य जल एवं सिंचाई के लिए सामान्य जल की उपलब्धता एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसे ग्रामीण आधार संरचना विकास की कार्ययोजना का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

1.68 आने वाले समय में जल एक दुर्लभ संसाधन बनता जाएगा। मानसून की असफलता के कारण भारतीय कृषि के नुकसान ने इस बात की ओर पुन: अधिक ध्यान केन्द्रित किया है कि किस प्रकार इस दुर्लभ संसाधन का उपभोग एवं उपयोग सर्वोत्तम रूप में किया जाये। इस बात पर भी फिर से विचार किया जाना चाहिए कि क्या देश खुली सिंचाई की पद्धति को अपनाये रख सकता है, जिसमें काफी जल की बर्बादी होती है, और सिंचाई की अन्य अधिक किफायती प्रणालियों को अपनाने का भी आकलन किया जाना चाहिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी), जिसका उद्देश्य केन्द्रीय ऋण सहायता के द्वारा सिंचाई सुविधायें स्थापित करने में राज्यों की मदद करना है, ने 1 फरवरी, 2002 से अपने ''फास्ट ट्रैक प्रोग्राम'' के अधीन एक वर्ष के अंदर पूरी की जाने वाली अनुमोदित बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण केन्द्रीय सहायता का आश्वासन दिया है। विद्यमान जलसंभर विकास कार्यक्रमों उदाहरणार्थ एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की इच्छा से 27 जनवरी, 2003 से एक नई शुरूआत 'हरियाली' शुरू की गई है। फिर भी, महत्वपूर्ण है, लागत वसूलियों के लिए सक्षम तंत्र हेतु व्यवस्था ताकि न केवल प्रचालन व रखरखाव के लिए समुचित निधियां सुनिश्चित की जा सकें बल्कि प्रयोक्ता भागीदारी और जल संरक्षण की भावना भी प्रोत्साहित की जाए।

1.69 कृषि के लिए संस्थागत ऋण का प्रवाह वर्ष 2000-01 में 14 प्रतिशत की तुलना में तेजी से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 21 प्रतिशत हो गया है। इससे वर्ष 2001-02 में कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सितंबर, 2002 तक 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस स्कीम में 31 मार्च, 2004 तक सभी पात्र किसानों को शामिल करने का इरादा है और यह अपने लाभार्थियों को व्यक्तिगत बीमा सुरक्षा (दुर्घटना से मौत, स्थायी अपंगता, आदि के लिए) भी प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम जिसका सब फसलों तक विस्तार किया गया है, में रबी, 2001-02 तक 20 मिलियन किसानों से अधिक को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम का क्रियान्वयन शीघ्र एग्रिकल्चर इन्श्यूरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा अधिग्रहीत कर लिया जाएगा जो अब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकरण की प्रतीक्षा में है। साधारण बीमा निगम, नाबार्ड और चार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा 1,500 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से स्थापित इस नये निगम का उद्देश्य फसल बीमा के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण/कृषि संबंधी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना भी है। स्वसहायता समूहों और अन्य वृहद्-ऋण संस्थाओं की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए, और समुचित विनियामक प्रणालियों के साथ लेनदेनों की लागत घटाकर और चूक के जोखिम को न्यूनतम करते हुए बैंकों से किसानों को कुशलतापूर्वक आगे धन उधार देने की स्थानीय स्थितियों की जानकारी रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों के समर्थन को सूचीबद्ध

करने के लिए एक पर्याप्त आधर विद्यमान है। कृषि बीमा में निजी बीमाकर्ताओं की प्रतिभागिता प्रतिस्पर्धा बाजार के लाभ भी उपलब्ध कराएगी।

1.70 उत्पादित कृषि उत्पादों की विपुल विविधता के बावजूद देश का वार्षिक कृषि निर्यात मूल्य 6 बिलियन डालर से कम है, इन निर्यातों में समुद्री उत्पाद अकेले 20 प्रतिशत बैठते हैं। कृषि में देश के दोहन न की गई निर्यात संभाव्यता के दोहन के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य उत्पाद आदेश, मांस उत्पाद आदेश तथा भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित निषेधात्मक खाद्य मानकों, जैसी विनियामक अक्षमताओं को हटाना आवश्यक है। चालू वर्ष के दौरान, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वस्तुओं की संख्या घटाकर 18 कर दी गई है। देश में साझे बाजार की स्थापना के उद्देश्य से छः कृषि उत्पादों की आवाजाही और भंडारण पर से प्रतिबंध हटा दिये गये हैं। चीनी तथा चाय सहित बयालिस वस्तुओं के वायदा कारोबार की अनुमति दी गई है। तथापि, कृषि उत्पादकों को सीधे नए बाजारों में पहुंच की अनुमति देते हुए कृषि विविधीकरण के उन्नयन हेतु कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। कृषि राज्य का विषय है इसलिए राज्यों को तत्काल कार्रवाई करनी होगी। चालू वर्ष में अपनाए गए सुधारों के उपायों से कृषि में निजी निवेश के नए मार्ग खुलने की संभावना है और इनसे वैश्विक बाजारों के लिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधरने के साथ मूल्य वर्धन की नींव भी पड़ेगी।

1.71 सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के तलचिह्नांकन के साथ भारत में प्रौद्योगिकी व प्रतिस्पर्धा के बीच वास्तविक अन्योन्यक्रिया के लिए एक समर्थकारी माहौल की आवश्यकता होगी, और इसे तीन कारकों– समुचित सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचा; उपर्युक्त विनियामक ढ़ांचा व सक्षम कर प्रणाली; और वृहद् आर्थिक स्थायित्व, द्वारा सुकर बनाने की आवश्यकता होगी।

1.72 संकेन्द्रित ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र निरक्षरता उन्मूलन, शिशु व जच्चा मृत्यु दर कटौती, मलेरिया व पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन, सड़कों, रेलमार्गों, पत्तनों व वायुपत्तनों के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था, विश्वसनीय और युक्तिसंगत मूल्य वाली विद्युत आपूर्ति, तथा स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता है। सार्वजनिक निधियों के उत्तोलन के लिए आधारभूत ढांचे में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने, सेवा परिदाय की गुणवत्ता में सुधार करने और धन के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री द्वारा अक्तूबर, 1998 में शुरू किए एनएचडीपी के अंतर्गत प्राप्त सफलता दर्शाती है कि इस क्षेत्र में वित्तपोषण और सार्वजनिक निजी भागीदारियों के नए तरीकों की काफी संभावना है। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के सवंर्धन में प्राप्त सीमित सफलता को बढ़ाने और देश के विकास में महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने वाले सुधारों को गति देने की आवश्यता है। सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के संवर्धन द्वारा स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में सुधार की काफी संभावना है। आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप को परिवर्तित कर उसे वस्तुतः सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रदायक बना दिया जाए चाहे वह उन्हें अनिवार्यतः स्वयं उत्पादित न करें।

1.73 विनियामक ढांचे व उपयुक्त कर प्रणाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। उदाहरणार्थ, भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण, राज्य विद्युत विनियामक आयोग, भारतीय बीमा विनिमायक प्राधिकरण तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कुछ समय से प्रचालन कर रहे हैं। संसद द्वारा प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2001 भी पारित कर दिया गया है। तथापि, कृषि में विनियामक तंत्र में आमूल सुधार करने की आवश्यकता है। श्रम बाजार सुधार और लघु उद्योग के आरक्षण का प्रश्न एक सन्निकट संवर्धित मुद्दा है। देश द्वारा लोचशील श्रम-बाजारों के अंतर्गत चल रहे बड़े संस्थानों में उत्पादित गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर बिक्री वैश्विक बाजार उपभोक्ता को की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अवैयक्तिक और मूल्यांकिती व कर अधिकारी के बीच न्यूनतम अंतरापृष्ठ वाले कुशल कर प्रशासन की ओर संचलन के साथ कर प्रणाली की पुनर्संरचना और केंद्रीय उत्पाद शुल्क व राज्य बिक्री कर के क्षेत्र में न्यूनतम छूटों की प्रणाली तथा मूल्यवर्द्धित कर की ओर एक पहल अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2003 से राज्यों द्वारा वैट की ओर प्रस्तावित संचलन न्यूनतम प्रपातकारी प्रभावों वाला सक्षम व स्वप्रवर्तनकारी घरेलू कर प्रणाली की स्थापना में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा। केंद्रीय बिक्री कर की दर में कमी और कुछ समय बाद इसकी समाप्ति एक एकीकृत भारतीय साझे बाजार की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम होंगे।

1.74 भारत राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के उपयुक्त संयोजन के अनुसरण के माध्यम से वृहद् आर्थिक स्थायित्व की तरफ बढ़ रहा है। जबकि मंद अभिवृद्धि विरोधी-चक्रीय-नीतियों के कारण है, राजकोषीय समेकन के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में वर्ष 1996-77 में 4.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 5.9 प्रतिशत हो गया है और सामान्य सरकार (अर्थात् समेकित केंद्र व राज्य) के लिए वर्ष 1999-2000 में 9.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 10.0 प्रतिशत हो गया है। जबकि ब्याज की दर अर्थव्यवस्था की अभिवृद्धि दर से नीचे बनी हुई है, उच्च प्राथमिक घाटों (ब्याज संदाय घटाकर राजकोषीय घाटा) के कारण सकल घरेलू उत्पाद के प्रति घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के प्रति ऋण, दोनों अनुपातों में प्रगामी रूप से बढ़ोतरी हुई है। ऋण में वृद्धि के साथ संबद्ध उच्च ब्याज संदाय के परिणामस्वरूप ब्याज संदायों, पारिश्रमिक व वेतन तथा पेंशनों द्वारा केंद्र के साथ-साथ राज्यों, दोनों की राजस्व प्राप्तियों के बहुत बड़े अनुपात का पूर्वक्रय हुआ हैं। राजकोषीय समेकन के बिना, पहले से ही दृष्टिगोचर अभिवृद्धि के सुधार के सूचकांक को देखते हुए यह जोखिम है कि सामान्य सरकार द्वारा संसाधनों का पूर्वक्रय निजी निवेश में उदीयमान सुधार को निष्प्रभावी कर देगा।

1.75 राजकोषीय समेकन के लिए राजस्व बढ़ाने व व्यय घटाने की द्विमुखी कार्य योजना की आवश्यकता है। कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाने के लिए एक दक्ष कम्प्यूटरीकृत व अवैयक्तिक कर प्रणाली आवश्यक है। कर-भिन्न राजस्व में समुचित प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से बेहतर लागत वसूली की स्पष्ट आवश्यकता है। व्यय के मोर्चे पर पारिश्रमिक, वेतन व पेशनों को नियंत्रण में लाना महत्वपूर्ण है। बाजार से जुड़ी ब्याज दरों में घट बढ़ के अनुरूप सरकार द्वारा जुटाई गई लघु बचतों पर ब्याज की दर संशोधित करने की आवश्यकता है। किसी भी सफल व्यय यौक्तिकीकरण और पुनः वरीयता कार्यक्रम से खाद्य, उर्वरक, एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतों को युक्तिसंगत बनाये जाने के माध्यम से सब्सिडियों के मुद्दे का हल होना चाहिए। योजनाओं की भूमिका, योजनाओं के लिए सकल बजटीय सहायता और आयोजना व्यय राजकोषीय घाटे व ऋण पर प्रतिकूल प्रभाव क्यों डालता है, सहित संघीय राजकोषीय अंतरणों के पूरे मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है।

1.76 भारत के खाद्यान्नों सहित अनेक निर्यात योग्य कृषीय उत्पादों के अतिशेष उत्पादक के रूप में उभरने से देश की खाद्य अर्थव्यवस्था का दक्ष प्रबंधन हाल के वर्ष में एक प्रमुख नीतिगत मुद्दा बन गया है। किन्तु चावल तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों ने कुछ फसलों के तुलनात्मक तथा क्षेत्रीय लाभ को समाप्त कर दिया है जिससे अतिशेष (चीनी, चावल, गेहूं) तथा कमियां (तिलहन, दालें तथा रेशे) दोनों का सृजन हुआ है। भारी खाद्य भंडारों का संग्रहण न केवल कृषि अभिवृद्धि और विविधीकरण पर बल्कि राजकोषीय घाटे पर भी चालू खाद्य प्रबंधन नीति के प्रभाव के संदर्भ में गंभीर मुद्दा बना हुआ है। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में न्यूनतम समर्थन मूल्य का औचित्य सिद्ध हुआ है। ऐसी ही आम सहमति है कि देश के गरीब व असुरक्षितों को आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कुछ खाद्य सब्सिडी पूर्णतया अनिवार्य है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (30 करोड़ से अधिक) को सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अत्यधिक गरीबी दूर करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व नवीन उपाय अन्त्योदय अन्न योजना है जो सर्वाधिक गरीबों के एक भाग (लगभग 6 करोड़) को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह, गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम के निम्न मूल्य पर , प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तथापि यह मानना महत्वपूर्ण है कि हमारे खरीद के तरीकों में गंभीर विरुपण आ गया है तथा साथ ही ये खाद्यान्नों में निजी व्यापार की भूमिका को समाप्त करते हैं जिससे केंद्र सरकार की सब्सिडी वचनबद्धता गम्भीर हो रही है। बफर ढुलाई लागतों के साथ-साथ खरीद लागतों को कम खर्चीला करने की आवश्यकता है जो खरीद में राज्यों की भागीदारी से ही संभव हो सकता है। भारतीय खाद्य निगम अब गंभीर अमितव्ययिता का सामना कर रहा है क्योंकि अब यह अनाज की सामान्य मात्रा से लगभग तीन गुणा प्रमात्रा की खरीद व भंडारण कर रहा है।

1.77 चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में फारस की खाड़ी में तेजी से बढ़ता हुआ तनाव देखा गया है। मध्यपूर्व में बढ़ती हुई शत्रुता की संभावना ने वर्ष 2003 में वैश्विक सुधार की गति में संदेह उत्पन्न कर दिया है। वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में उच्च वृद्धि के साथ, आगामी महीनों में उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर विकासशील एशिया की अर्थव्यवस्थाओं की अभिवृद्धि संभावनाओं के बारे में गंभीर चिंताएं हैं। केंद्रीय पूल में रखे भारी खाद्य भंडारों के साथ ही

देश में रखे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों की भारी प्रमात्रा ने इस अनिश्चित वैश्विक स्थिति में देश को सुखद स्थिति में रखा है। प्रारक्षित भंडारों के 70 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने से भारत उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में प्रारक्षित मुद्रा धारण करने वाले शीर्षस्थ देशों में से एक है। विश्व में तेल मूल्यों में तीव्र वृद्धि या अन्य बहिर्जात घटनाओं की स्थिति में देश ऊंचे आयात बिलों के वित्तपोषण में सक्षम है। तथापि, मध्य पूर्व में लंबे टकराव से विकासशील एशिया की अनेक अर्थव्यवस्थाओं की निर्यात संभावनाओं पर, उनके अमरीकी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रभाव पड़ने की संभावना है। निर्यात संभावनाओं में मामूली दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र अभिवृद्धि निष्पादन पर आने वाले महीनों में घरेलू मांग में पुनरूज्जीवन के स्पष्ट संकेतों और घरेलू आर्थिक गतिविधि को मिली परिणामी उत्प्लावकता के कारण खाड़ी में घटनाक्रमों से गंभीर रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तो भी, निरंतर आधार पर संतुलित अभिवृद्धि की नींव सुदृढ़ करने के लिए तीन मुद्दों–आधारभूत ढांचा, विनियामक तथा कर प्रणाली सुधार व राजकोषीय समेकन के निवारण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।